हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - CTHIN/25/A0716

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 211 बेमेतरा, गुरुवार 26 मार्च 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 5 रूपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

किसानों की खुशियों भरी होली के बाद अब भूमिहीन कृषि श्रमिकों की नवरात्रि हुई समृद्ध

रायपुर। किसानों की खुशियों भरी होली के बाद अब भूमिहीन कृषि श्रमिकों के लिए भी यह नवरात्रि समृद्धि और आत्मविश्वास का संदेश लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में सुशासन सरकार की योजनाएं अब सीधे जनजीवन में परिवर्तन का आधार बनती दिख रही हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बलौदाबाजार जिले में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 4 लाख 95 हजार 965 भूमिहीन कृषि मजदूरों के खातों में 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये की राशि अंतरित की। उन्होंने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि श्रम और सम्मान को सशक्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत किए गए वादों को सरकार द्वारा तेजी और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जा रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि धान खरीदी में अंतर की राशि मिलने से किसानों ने इस वर्ष उत्साह और संतोष के साथ होली मनाई, वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिली राशि ने उनके आत्मनिर्भरता के संकल्प को और मजबूत किया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक रूप से गृह प्रवेश कराते हुए मकानों की चाबियां भी सौंपीं। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिससे हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का नया अध्याय जुड़ा है। मुख्यमंत्री साय ने बलौदाबाजार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का स्मरण करते हुए बाबा गुरु घासीदास, संत कबीर और शहीद वीर नारायण सिंह को नमन किया।

उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपये की सहायता राशि भूमिहीन कृषि मजदूरों को दी जा रही है, जिससे वे अपने परिवार की आवश्यकताओं, बच्चों की शिक्षा और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने में सक्षम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादे के अनुरूप 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण दर में वृद्धि, चरण पादुका योजना का पुनः संचालन तथा रामलला दर्शन एवं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आध्यात्मिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बिजली बिल समाधान योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि कोरोना काल में लंबित बिलों के निपटान हेतु विशेष छूट एवं आसान किस्तों की सुविधा प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा—नक्सलवाद अब अंतिम पड़ाव पर, बस्तर में गूंज रही विकास की आवाज़

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बस्तर संभाग के जगदलपुर में मोस्ट वॉन्टेड हार्डकोर नक्सली कमांडर पापाराव ने अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। यह घटनाक्रम बस्तर में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस आत्मसमर्पण को नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार बताते हुए कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और बस्तर की धरती पर हिंसा की विचारधारा पराजित होती स्पष्ट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक भय और हिंसा का वातावरण बनाने वाली माओवादी विचारधारा अब समाप्ति की ओर है और बस्तर तेजी से विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की पारदर्शी, संवेदनशील और पुनर्वास केंद्रित नीतियों के कारण भटके हुए युवा अब मुख्यधारा में लौटने का विश्वास पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आत्मसमर्पण इस बात का प्रमाण है कि यदि सही अवसर, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिले, तो हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के मार्ग को अपनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर में बंदूक की आवाज़ नहीं, बल्कि विकास, विश्वास और नई उम्मीदों की गूंज सुनाई दे रही है।

सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से हो रहे कार्यों ने बस्तर के जनजीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। मुख्यमंत्री साय ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सशक्त मार्गदर्शन को देते हुए कहा कि नक्सलमुक्त भारत का संकल्प अब निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने सुरक्षाबलों के साहस, समर्पण और रणनीतिक कार्रवाई की भी सराहना की।

संक्षिप्त समाचार

नौ राज्यों को एफएमडी मुक्त घोषित कर डेयरी निर्यात बढ़ाने की योजना : सरकार

नयी दिल्ली। देश के नौ राज्य खुरपका-मुंहपका रोग से मुक्त हो चुके हैं और उन्हें इसका प्रमाणन दिलाकर देश का डेयरी निर्यात बढ़ाने की सरकार की योजना है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके बावजूद डेयरी उत्पादों के निर्यात में हम पीछे हैं क्योंकि कई देशों में डेयरी निर्यात के लिए एफएमडी मुक्त प्रमाणन जरूरी है। सिंह ने कहा कि साल 2014-15 में हमारा दुग्ध उत्पादन 14.63 करोड़ टन से बढ़कर 24.8 करोड़ टन हो गया है।

सभी नागरिकों के लिए समान कानून भाजपा की प्राथमिकता : अमित शाह

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रही है कि देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले। गुजरात विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने पर शाह ने यह बात कही। शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, देश में हर नागरिक के लिए एक समान कानून हो, यह भाजपा का स्थापना से ही संकल्प रहा है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा की राज्य सरकारें इस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही हैं। मुझे हर्ष है कि उत्तराखंड के बाद अब गुजरात ने भी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कार्य कर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और इस विधेयक को समर्थन देने वाले सभी विधायकों को बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि देश तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून से चले, यह हमारी प्राथमिकता भी है और संकल्प भी है।

एलपीजी रिफिल बुकिंग की समय-सीमा निर्धारित

नई दिल्ली। सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ समाचार रिपोर्ट और सोशल मीडिया पोस्ट में एलपीजी रिफिल बुकिंग की संशोधित समय-सीमा का दावा किया जा रहा है। इनमें पीएमयूवाई कनेक्शन के लिए 45 दिन, गैर-पीएमयूवाई सिंगल बॉटल कनेक्शन के लिए 25 दिन और गैर-पीएमयूवाई डबल बॉटल कनेक्शन के लिए 35 दिन बताया जा रहा है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। रिफिल बुकिंग की मौजूदा समय-सीमा पूर्ववत बनी हुई है जो शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन, कनेक्शन की श्रेणी से कोई सरोकार नहीं। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं तथा एलपीजी रिफिल की अनावश्यक या घबराहट में बुकिंग से बचें।

ट्रेनों में 78 प्रतिशत सीटें सामान्य स्लीपर क्लास की हैं : वैष्णव

नयी दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोक सभा में बताया कि ट्रेनों में 70 प्रतिशत स्लीपर और सामान्य डिब्बे लगाये गये हैं। वैष्णव ने प्रश्नकाल में बताया कि कुल ट्रेनों में 78 प्रतिशत सीटें स्लीपर और सामान्य डिब्बों की हैं। उन्होंने बताया कि गर्मियों और त्योहारों के समय तथा भीड़ बढ़ने के दौरान बड़ी संख्या में विशेष ट्रेन चलायी गयी हैं, जिससे यात्रियों को बहुत सहूलियत हुई है।

व्यवसाय बढ़ाने तथा करदाताओं को आसानी हो

वित्त विधेयक 2026 लोकसभा में ध्वनिमत से पारित

नयी दिल्ली। लोकसभा ने वित्त वर्ष 2026-2027 में सरकार के बजट प्रस्तावों को लागू करने के लिए अहम वित्त विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में वित्त विधेयक पर दो दिन चली चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए करो में सुधार कर कारोबार को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि विदेश जाने वाले पर्यटकों के लिए करो में छूट दी गई है और जो विदेश से जरूर का सामान लाते हैं उनको एयरपोर्ट पर दिक्कत ना हो इसे निर्बाध और सरल बनाने का काम किया गया है। उनका कहना था कि आयकर व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हुए इसका सरलीकरण किया गया है ताकि लोगों को व्यवसाय बढ़ाने तथा करदाताओं को आसानी हो। वित्त मंत्री ने कहा कि राजकोषीय घाटा कम करना उनकी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसे धीरे धीरे कम किया जा रहा है। उनका कहना था की 2020-21 राजकोषीय घाटा 9.3 प्रतिशत था जो अब तक 4.3 प्रतिशत काम हुआ है। इसी तरह से विश्व स्तर में ऋण में भी भारत, चीन, जापान और अमेरिका जैसे देश से कई अधिक बेहतर स्थिति में है। उनका कहना था कि देश का आर्थिक आधार मजबूत है और अब कोई भी बड़ा संकट सरकार की आर्थिक आधार को कमजोर नहीं कर सकता है। उनका कहना था कि 2008 के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के समय में आये मामूली आर्थिक संकट ने सरकार को हिला दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जो सुधार कर रही है वे मजबूरी में नहीं बल्कि स्पष्ट मंशा और विश्वास दृढ़ विश्वास के साथ किये जा रहे है। उनकी सरकार राष्ट्र निर्माण के विकास की सतत प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। यह कार्य एक रात में होने वाला नहीं है। देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सुधार हो रहे गेन और ये सुधार किसी दबाव में नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ किए जा रहे हैं और देश में सुधारों की प्रक्रिया स्टेट गई और 'एक्सप्रेस-वे' पर आगे बढ़ रही है। सरकार का फोकस भरोसे पर आधारित कर व्यवस्था बनाने पर है, जिसके तहत ईमानदार करदाताओं के लिए परेशानियां कम की जा रही हैं।

रामावतार जग्गी हत्याकांड : उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दोबारा सुनवाई

बिलासपुर। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में प्रदेश के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड मामले की पुनः सुनवाई हुयी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई। अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए एक अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान मृतक रामावतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी भी अदालत में उपस्थित रहे। गौरतलब है कि इससे पहले उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने लगभग दो वर्ष पूर्व इस मामले में दोषियों की अपील खारिज करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा था। हालांकि, बाद में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने मामले की पुनः विस्तृत सुनवाई के लिए इसे उच्च न्यायालय भेज दिया, ताकि मामले के मेरिट पर गहन परीक्षण किया जा सके। रामावतार जग्गी की हत्या के बाद प्रारंभिक पुलिस जांच पर पक्षपात और असंतोष के आरोप लगे थे। इसके चलते राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई की जांच में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी सहित कई लोगों को हत्या और आपराधिक साजिश का आरोपी बनाया गया था।

भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने से हाईकोर्ट का इंकार, दिए जांच का आदेश

छत्तीसगढ़ में पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर चल रहे विवाद पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पूरी भर्ती प्रक्रिया और अंतिम चयन सूची को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि भर्ती में व्यापक स्तर पर अनियमितता साबित नहीं हुई है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना न्यायसंगत नहीं होगा। यह फैसला जस्टिस पी.पी. साहू की सिंगल बेंच द्वारा सुनाया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं की मांगों पर विस्तार से विचार किया गया। दरअसल, पुलिस विभाग द्वारा निकाली गई कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।

भारत में ईंधन का कोई संकट नहीं : सरकार

नयी दिल्ली। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक खबरों के बीच केन्द्र और राज्य संचालित तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पिछले 48 घंटों के दौरान पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें तेजी से फैलीं, जिससे देश के कुछ हिस्सों में लोगों में चिंताएं बढ़ी और कुछ पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखी गई। हालांकि अधिकारियों ने इन आशंकाओं को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि भू-राजनीतिक तनाव के बावजूद भारत की ईंधन सुरक्षा मजबूत बनी हुई है। एक विस्तृत परामर्श में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने नागरिकों को आश्वस्त किया है कि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सभी आपूर्ति श्रृंखलाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं। कंपनी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपीसीएल ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह निराधार हैं। भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है। बीपीसीएल पूरी तरह संचालन में है और निर्बाध ईंधन आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और भारत इन ईंधनों का शुद्ध निर्यातक है। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा नहीं है।

अमेरिका ने ईरान को युद्ध समाप्त करने के लिए भेजा 15 सूत्री योजना

तेहरान ने बातचीत से किया इनकार

वाशिंगटन। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव दिया है जो 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक पहल हो सकती है। हालांकि ईरान ने किसी भी प्रकार की बातचीत होने से स्पष्ट इनकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान में मध्यस्थों के माध्यम से भेजा गया था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी इस मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से इस योजना की पुष्टि की है। लगभग चार सप्ताह पहले 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के अंतर्गत अमेरिका और इज़रायल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के बाद बढ़ते संघर्ष के बीच यह राजनयिक प्रयास किया जा रहा है। इसके जवाब में, ईरान ने इज़रायली शहरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और होर्मुज़ जलडमरूमध्य से पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों के आवागमन को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित किया है।

इस बीच, ईरान और लेबनान पर इज़रायल के हमले जारी हैं और तेल अवीव के चैनल 12 ने प्रस्ताव के प्रमुख बिंदुओं की रिपोर्ट दी, जिसमें अमेरिकी मांगों और संभावित रियायतों दोनों की रूपरेखा दी गई है, हालांकि किसी भी सरकार ने आधिकारिक रूप से पूरा दस्तावेज़ जारी नहीं किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वाशिंगटन ईरान में सही लोगों से बातचीत कर रहा है और दावा किया कि तेहरान समझौते पर पहुंचने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष 15 बिंदुओं पर सहमत हुए हैं जिनमें ईरान द्वारा परमाणु हथियार हासिल न करने की प्रतिबद्धता भी शामिल है। ट्रम्प ने यह भी सुझाव दिया कि अगर कोई समझौता हो जाता है तो होर्मुज जलडमरूमध्य जल्द ही फिर से खुल सकता है और संकेत दिया कि इस तरह की व्यवस्था के तहत ईरान के समृद्ध यूरेनियम भंडार को अमेरिका द्वारा अपने कब्जे में लिया जा सकता है। ईरानी अधिकारियों ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वाशिंगटन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है।

झंडेवालान मंदिर के पास स्लीपर बस पलटी, हादसे में 2 की मौत, 23 घायल

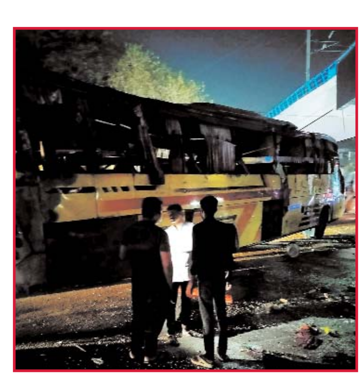

नई दिल्ली। करोल बाग इलाके में स्थित झंडेवालान मंदिर के पास मंगलवार तड़के एक स्लीपर टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 यात्री घायल हो गए। पुलिस और स्थानीय लोगों की त्वरित कार्रवाई से बस में फंसे यात्रियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक 25 मार्च 2026 को करीब 1:05 बजे पीसीआर कॉल के जरिए सूचना मिली कि करोल बाग के हनुमान मंदिर के पास एक स्लीपर बस पलट गई है और कई यात्री घायल हैं। यह बस टूरिस्ट स्लीपर बस थी, जो जयपुर से दिल्ली के फतेहपुरी, सदर बाजार की ओर जा रही थी। बस में हादसे के समय करीब 30 यात्री सवार थे।

लोगों की मदद से पुलिस ने शुरू किया रेस्क्यू

सूचना मिलते ही करोल बाग थाने की टीम मौके पर पहुंची। उस समय बस पलटी हुई थी और कई यात्री अंदर फंसे हुए मदद के लिए चिल्ला रहे थे। पुलिसकर्मियों ने तुरंत एक गुजर रही जेसीबी मशीन को रुकवाया और स्थानीय लोगों की मदद से बस को हल्का उठाकर सीमेंट के ब्लॉकों से सहारा दिया। इसके बाद राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। सबसे पहले करीब 10 गंभीर घायलों को एंबुलेंस की मदद से सर गंगाराम अस्पताल भेजा गया। बाद में अन्य पुलिस अधिकारियों और टीमों के पहुंचने के बाद बाकी यात्रियों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया।

आरएमएल में हुई दो यात्रियों की मौत

कुल 23 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से 12 को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां दो पुरुषों की मौत हो गई। 10 को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया और एक को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मृतकों में से एक की पहचान शहबाज आलम (30) के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर गांव का रहने वाला था। दूसरे मृतक (लगभग 25-26 वर्ष) की पहचान अभी नहीं हो सकी है और पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है। बस चालक पंकज कुमार (26) निवासी अलवर, राजस्थान भी घायल है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है।

रसूखदार हो या बड़े नेता, अफीम की खेती में संलिप्त आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे: सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अफीम की अवैध खेती, विदेश नीति और नक्सलियों के आत्मसमर्पण जैसे मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में कहीं भी अफीम की खेती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसमें शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सीएम साय ने कहा कि जब दुर्ग जिले में अफीम की खेती का मामला सामने आया था, तभी सभी कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए गए थे। कई जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई कर खेती को चिन्हांकित भी किया है। उन्होंने दो टूक कहा कि चाहे कितने भी बड़े रसूखदार क्यों न हों, सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मुद्दे पर कलेक्टरों की बैठक भी ली गई थी और उनसे जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार की विदेश नीति को कमजोर बताने पर सीएम साय ने पलटवार करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के मजबूत नेता हैं और उनकी विदेश नीति प्रभावी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए रास्ते खुले हैं और गैस व तेल की आपूर्ति भी सुगम हुई है। नक्सलियों के सरेंडर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का स्पष्ट संकल्प है कि देश से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। 31 मार्च की समय सीमा के बीच लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और पापाराव जैसे बड़े नक्सलियों का सरेंडर होना सकारात्मक संकेत है। सीएम साय ने इसे राज्य और देश के लिए अच्छी खबर बताते हुए कहा कि सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

चांपा स्टेशन पर 'लैंड ऑफ कोसा सिल्क' मूर्ति को लेकर विवाद, नगर की पहचान बदलने की साजिश के आरोप

चांपा/मूक पत्रिका

बरसों से कोसाङ्ककांसाङ्ककंचन नगरी के रूप में पहचानी जाने वाली चांपा की ख्याति पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। चांपा रेलवे स्टेशन के मुख्य गेट के सामने ÷चांपा लैंड ऑफ कोसा सिल्क÷ नाम लिखी मूर्ति लगाए जाने की तैयारी को लेकर नगर में तीखी चर्चा और असंतोष का माहौल बन गया है। नगरवासियों का कहना है कि इस तरह की पहचान थोपने से चांपा की पारंपरिक और ऐतिहासिक पहचान को नुकसान पहुंच सकता है। चांपा न केवल जांजगीर-चांपा जिला, बल्कि पूरे प्रदेश और देश में कोसा, कांसा और कंचन की नगरी के रूप में जानी जाती रही है। ऐसे में केवल कोसा सिल्क को केंद्र में रखकर मूर्ति लगाने को लेकर नगर की जनता के बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह जानबूझकर नगर की बहुआयामी पहचान को सीमित करने का प्रयास है। नगरवासियों के बीच चर्चा है कि कहीं यह कदम कोसाङ्ककांसाङ्ककंचन की समृद्ध परंपरा को कमजोर करने की साजिश तो नहीं। कुछ लोग इसे प्रशासनिक लापरवाही बता रहे हैं, तो कुछ इसे सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि कांसा और कंचन को दरकिनार कर केवल कोसा सिल्क को प्रमुखता देने के पीछे आखिर किसकी मंशा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे स्टेशन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थल पर लगने वाली मूर्ति नगर की पहचान का प्रतीक होती है। ऐसे में यदि पहचान अधूरी या एकतरफा दिखाई गई, तो आने वाले समय में चांपा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है। बहरहाल, नगर की जनता यह जानना चाहती है कि ÷चांपा लैंड ऑफ कोसा सिल्क÷ नाम की मूर्ति किसके आदेश पर और किस आधार पर स्थापित की जा रही है। क्या इस निर्णय में जनप्रतिनिधियों या नगर की सामाजिक संस्थाओं से राय ली गई? या फिर यह फैसला चुपचाप ले लिया गया? फिलहाल यह मुद्दा नगर के कई व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो चुका है और लोग खुलकर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। नगरवासियों को अब प्रशासन और संबंधित विभाग से स्पष्ट जवाब का इंतजार है कि चांपा की सदियों पुरानी पहचान के साथ कोई समझौता तो नहीं किया जा रहा।

4 साल पुराने अंधे कत्ल का खुलासा, दूसरी शादी के विवाद में तीन आरोपी गिरफ्तार

कांकेर/मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर/:-कांकेर 25 मार्च 2026 थाना ताड़ोकी क्षेत्र में वर्ष 2022 में हुए अंधे हत्या प्रकरण का पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह मामला 13 जुलाई 2022 का है, जब ग्राम सरंडी निवासी संदेश कुमार ध्रुव की संदिग्ध मृत्यु की सूचना पर मर्ग कायम किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

जांच के दौरान सामने आया कि मृतक की दूसरी शादी की बात को लेकर गांव में विवाद चल रहा था। इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने योजना बनाई। 13 जुलाई 2022 की रात लगभग 8:30 बजे आरोपी गंगूराम ध्रुव (39 वर्ष), रजऊ राम ध्रुव (42 वर्ष) एवं मंगूराम ध्रुव (34 वर्ष) मृतक के घर पहुंचे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, लंबे समय तक मामला अनसुलझा रहा। पुलिस के अनुसार, पहले क्षेत्र में नक्सल प्रभाव अधिक होने के कारण घटनास्थल तक पहुंचकर गहन जांच करना कठिन था। हाल के समय में नक्सल गतिविधियों में कमी आने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और संदिग्धों से पूछताछ तेज की। 23 मार्च 2026 को गहन पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद 24 मार्च 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस पूरे प्रकरण के खुलासे में थाना ताड़ोकी एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन:

इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक निखिल अशोक कुमार राखेचा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष बंछोर (अंतागढ़), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा (साइबर नोडल) तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी गिरीशंकर साव के निर्देशन व पर्यवेक्षण में टीम ने सफलता प्राप्त की।

रेत के अवैध परिवहन पर की गई कार्रवाईः 13 हाईवा व 3 ट्रैक्टर जब्त

जांजगीर-चांपा/मूक पत्रिका

कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर रोकथाम हेतु राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानो का औचक जांच किया गया। खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान रेत के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर अकलतरा क्षेत्र में 6 हाईवा, चांपा के हथनेवरा में 6 हाईवा व 3 ट्रैक्टर एवं पामगढ़ क्षेत्र में 1 हाईवा को जब्त कर कार्रवाई की गई। खनिजो के अवैध परिवहन के दर्ज प्रकरणों पर अवैध परिवहनकर्ताओं के विरूद्ध खांन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में खनिज विभाग द्वारा निरंतर जांच कार्यवाही की जा रही है, जो कि निरंतर जारी रहेगी।

हैदराबाद में ही बस गया वाराणसी!' एस. एस.राजामौली ने महेश बाबू की फिल्म के लिए खड़ा किया आलीशान सेट; साक्षात पवित्र शहर की दिख रही झलक

एस. एस. राजामौली ने अब तक की सबसे बड़ी फिल्म 'वाराणसी' के लिए हैदराबाद में एक विशाल सिनेमाई साम्राज्य खड़ा किया है, जिसमें महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में हैं।

जित मुम्बई/मूक पत्रिका

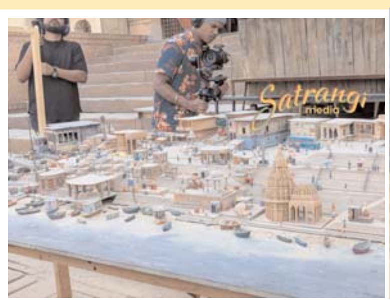

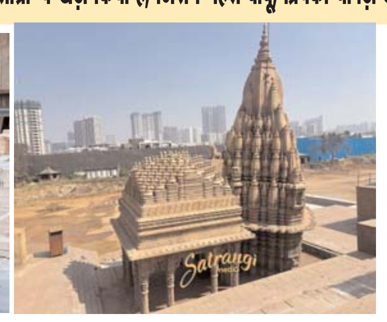

:- एस. एस. राजामौली भारत के सबसे बेहतरीन और विजनरी फिल्म मेकर्स में से एक हैं, जो हमेशा सिनेमा को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। उनकी फिल्में न केवल असल जिंदगी से बड़ी (लार्जर देन लाइफ) होती हैं, बल्कि कुछ ऐसा होती हैं जो पूरी दुनिया के दर्शकों तक पहुँचती हैं। मशहूर फिल्म मेकर अब अपनी अगली बड़ी एक्शन-एडवेंचर फिल्म, 'वाराणसी' के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा जोनस और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ यह फिल्म पहले ही देश के सबसे बेसब्री से इंतज़ार किए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से एक बन गई है। अभी इस फिल्म का प्रोडक्शन चल रहा है और यह हैदराबाद में लगाए गए शानदार सेटों के लिए खूब सुर्खियां बटोर रही है, जहाँ बड़े पैमाने पर वाराणसी की झलक को फिर से बनाया गया है। प्रतिष्ठित मंदिरों और आलीशान महलों के डिजाइन से लेकर बारीक से बारीक बनावट तक, ये सेट वाराणसी से इतने मिलते-जुलते हैं कि कोई भी यह महसूस किए बिना नहीं रह सकता कि वे साक्षात उसी पवित्र शहर के बीचों-बीच खड़े हैं। घाटों, मंदिरों और वहाँ के माहौल को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया है कि वाराणसी की रूह को पूरी तरह से उसमें उतारा जा सके, जिससे ये सेट एकदम असली नजर आ रहे हैं। पौराणिक कथाओं और एक्शन-एडवेंचर के मेल वाली कहानी के लिए बनाए गए ये विशाल सेट, मशहूर फिल्म मेकर राजामौली और उनकी टीम की मेहनत और लगन का सबूत हैं, जो दर्शकों को एक शानदार सिनेमाई अनुभव देना चाहते हैं। ये बड़े और असली दिखने वाले सेट बताते हैं कि मेकर्स चाहते हैं कि लोग फिल्म देखते हुए सीधे उस पवित्र शहर (वाराणसी) के समय में पहुँच जाएँ।भारत में फिल्म रिलीज होने से पहले ही 'वाराणसी' ने दुनिया भर में अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है। फिल्म की पहली झलक यूरोप के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित थिएटर 'ले ग्रैंड रेक्स' (ख्र तह्लड्डठ्ठस्र ऋद्ग×) के ट्रेलर फेस्टिवल में दिखाई गई, जहाँ फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। फिल्म के पहले फ्रेम से ही पूरा हॉल तालियों, शोर और सीटियों की आवाज से गूँज उठा, जो इस बात का इशारा है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस फिल्म को लेकर कितना तगड़ा बज बना हुआ है।चर्चा को और बढ़ाते हुए, 'वाराणसी' से महेश बाबू का 'रुद्र' के रूप में दमदार लुक, पृथ्वीराज सुकुमारन का 'कुंभा' के रूप में इंटेंस पहला लुक और प्रियंका चोपड़ा जोनस का 'मंदाकिनी' के रूप में रौबदार अवतार पहले ही सामने आ चुका है, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है और पूरे देश में एक्साइटमेंट भर दी है। इन शानदार झलकियों ने उम्मीदें बहुत बढ़ा दी हैं, और अब दर्शकों का इंतज़ार सातवें आसमान पर है क्योंकि हर कोई इस भव्य सिनेमाई अनुभव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है, जो 7 अप्रैल, 2027 को बड़े पर्दे पर एक ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु नवीनीकरण और नवीन आवेदन की अंतिम तिथि 27 मार्च

12वी से उच्चतर पढ़ाई कर रहे एसटी, एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को जमा करना होगा ऑनलाइन आवेदन

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सूचित किया गया है कि, वे शिक्षा सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति के लिए विभागीय पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन https://postmatric-scholarship.cg.nic.in में नवीनीकरण और नवीन आवेदन 27 मार्च 2026 तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद शिक्षा सत्र 2025-26 के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति के लिए विभागीय पोर्टल को बंद किया जाएगा।

छात्रवृत्ति हेतु पात्रता- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के पालक की आय सीमा रू. 2.50 लाख और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय सीमा 1 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम संलग्न करना होगा। पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अपने जिले के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग कार्यालय कोसीर रोड कालेज के पास सारंगढ़ से प्राप्त की जा सकती है।

सारंगढ़ जिले के किसान भी करेंगे मधुमक्खी पालन, नवीन तकनीकियो से 50 कृषकों ने लिया प्रशिक्षण

रायपुर /मूक पत्रिका

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल जी के मार्गदर्शन में डॉ. विवेक त्रिपाठी (निदेशक अनुसन्धान संचालक) एवं डॉ. एस.एस. टुटेजा (निदेशक विस्तार सेवाएँ) के निर्देशन में ÷ राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन ÷ के तहत् कृषि विज्ञान केंद्र ङ्कबोइरदादर रायगढ़ द्वारा दिनांक- 19.03.2026 से 25.03.2026 तक सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के 50 महिला एवं पुरुष कृषकों हेतु 7 दिवसीय प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया गया 7 जिसका समापन समारोह दिनांक- 25.03.2026 को डॉ. संजय कन्नौजे, कलेक्टर एवं जिलाधीश, संजय भूषण पांडे, अध्यक्ष जिला पंचायत सारंगढ़ , उमेश साहू, डिप्टी कलेक्टर, जिला- सारंगढ़-बिलाईगढ़ की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ 7 उक्त कार्यक्रम में डॉ. बी.एस.राजपूत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र ङ्क रायगढ़, आशुतोष श्रीवास्तव, उप संचालक कृषि, आकांक्षा उपाध्याय, सहायक संचालक उद्यानिकी, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़, डॉ. के.के. पैकरा, डॉ. सी.पी.एफ सोलंकी एवं डॉ. भोगेश्वरी साहू, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र- रायगढ़, दीपक कुमार बंजारे, प्र.वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सारंगढ़, जे.पी. गुप्ता, बोधराम सतनामी, मनीराम राम पैंकरा,भागवत प्रसाद सोनी, कृषि विकास अधिकारी सारंगढ़ एवं संबंधित क्षेत्रों के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं आत्मा योजनान्तर्गत कार्यरत बी.टी.एम एवं ए.टी.एम. उपस्थित रहे।

गल्ला से नकदी चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1500 रुपये बरामद

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले के थाना खम्हरिया क्षेत्र में जनरल स्टोर की दुकान से नकदी चोरी के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 1500 रुपये नगद बरामद किए गए हैं।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड क्रमांक 15 निवासी प्रभात अग्रवाल ने थाना खम्हरिया में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी ÷प्रभात किराना स्टोर÷ नाम से जनरल स्टोर की दुकान है। 22 मार्च की रात करीब 8 बजे दुकान बंद कर गल्ले में नगदी रखकर घर चले गए थे। अगले दिन 23 मार्च की सुबह दुकान खोलने पर गल्ले में रखे लगभग 10 से 12 हजार रुपये गायब मिले, जिसे अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया था।प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (ब्ह्रस्) की धारा 305(ए) एवं 331(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर पुलिस उप महानिरीक्षक रामकृष्ण साहू के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश कुमार यादव तथा एसडीओपी भुषण एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच तेज की गई।जांच के दौरान संदेही रोहित मंडावी (29 वर्ष), निवासी डबरापारा थानखम्हरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने चोरी की घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि चोरी की गई राशि में से अधिकांश रकम उसने खर्च कर दी, जबकि 1500 रुपये छिपाकर रखे थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से उक्त राशि बरामद कर ली।पुलिस ने आरोपी को 25 मार्च 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रदेव वर्मा, उप निरीक्षक ओंकार प्रसाद साहू, प्रधान आरक्षक अजय कुमार लहरे सहित थाना खम्हरिया के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

निर्धन परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन की राह में अभिनव पहलः विधायक साहू

भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिला आर्थिक संबल, खातों में पहुंची करोड़ों की राशि

हितग्राहियों के चेहरों पर मुस्कान, सरकार ने पहुंचाई सीधी मदद,

बेमेतरा/मूक पत्रिका

निर्धन और भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मज़दूर कल्याण योजना एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल के रूप में सामने आ रही है। इसी कड़ी में बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने योजना के हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की। जिला मुख्यालय मे कलेक्टरेट के दिशा सभाकक्ष मे कार्यक्रम का आयोजन किया गया 7

जिले के 19,113 हितग्राहियों को 19 करोड़ 11 लाख 30 हजार रुपए अंतरित- जिला बेमेतरा के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के 19,113 चिन्हित हितग्राहियों के खातों में कुल 19 करोड़ 11 लाख 30 हजार रुपए की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई। कार्यक्रम में प्रतीक स्वरूप जिले के 5 हितग्राहियों को अंतरित राशि का प्रमाण पत्र भी भेंट किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हितग्राहियों में उत्साह का वातावरण देखा गया।

आर्थिक स्वावलंबन और खुशहाली के लिए संचालित की जा रही योजना - साहू- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक साहू ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मज़दूर कल्याण योजना निर्धन परिवारों के आर्थिक स्वावलंबन और उनके जीवन में खुशहाली लाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में राज्य और केंद्र सरकार समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की चिंता करते हुए लगातार योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा से जोड़ने की रही है और यह योजना उसी सोच का परिणाम है। योजना से मिलने वाली राशि से भूमिहीन कृषक और मज़दूर परिवार अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकेंगे।

भूमिहीन कृषि मज़दूर परिवारों को मिलेगा आर्थिक संबलः कलेक्टर- इस अवसर पर कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवारों को संबल देने की दिशा में यह योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे कृषि मज़दूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिनके पास अपनी खेती योग्य भूमि नहीं है और जो पूरी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि मज़दूरों की भूमिका रीढ़ की हड्डी के समान होती है, लेकिन भूमिहीन होने के कारण वे अक्सर असुरक्षित स्थिति में रहते हैं। ऐसे परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की लाने की दिशा में यह योजना सार्थक साबित होगी।

पात्र हितग्राहियों को हर वर्ष मिलेंगे 10 हजार रुपए- उल्लेखनीय है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मज़दूर कल्याण योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को सरकार द्वारा प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

योजना के लागू होने से ऐसे परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा और वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। साथ ही स्थानीय स्तर पर आर्थिक सहायता मिलने से मजदूरों के शहरों की ओर पलायन पर भी रोक लगेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

नवागढ़, बेरला, साजा सहित सभी विकासखंडों में आयोजित हुए कार्यक्रम- अनुविभाग नवागढ़ अंतर्गत नवागढ़ तहसील में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मज़दूर कल्याण योजना के तहत हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसी प्रकार बेरला, साजा, बेमेतरा, नवागढ़ और जिले के अन्य विकासखंडों में भी कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में हितग्राही, ग्रामीणजन और किसान भाई उपस्थित रहे।

जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे उपस्थित- कार्यक्रम में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई, एसएसपी रामकृष्ण साहू, जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता पदमाकर, जनपद अध्यक्ष बेमेतरा हेमा दिवाकर, नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि अजय साहू, राजेंद्र शर्मा, राज्य किसान मोर्चा अध्यक्ष हर्षवर्धन सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और किसान उपस्थित रहे।

तहसील अधिवक्ता संघ चांपा में नवनिर्मित अधिवक्ता कक्ष का लोकार्पण, व्यवहार न्यायाधीश रहीं मुख्य अतिथि

चांपा/मूक पत्रिका

तहसील अधिवक्ता संघ चांपा में नवनिर्मित अधिवक्ता कक्ष का लोकार्पण समारोह तहसील परिसर में गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश वर्गङ्क01 श्रीमती नम्रता नोरगे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीरङ्कचांपा के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य जी.के. गुजराल एवं डीबी वेंचर्स चांपा के डायरेक्टर धीरेन्द्र बाजपेई विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के तैलचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया।

दीप प्रज्ज्वलन व्यवहार न्यायाधीश श्रीमती नम्रता नोरगे एवं उपस्थित विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया गया। इसके पश्चात नवनिर्मित अधिवक्ता कक्ष का फीता काटकर विधिवत लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने अधिवक्ताओं को नवीन कक्ष की सौगात मिलने पर बधाई दी और इसे न्यायिक कार्यों के सुचारु संचालन में सहायक बताया। अतिथियों ने कहा कि बेहतर अधिवक्ता कक्ष से अधिवक्ताओं को सुविधाजनक वातावरण मिलेगा, जिससे वादकारियों को भी लाभ होगा।

लोकार्पण समारोह के साथ नवरात्रि के पावन अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आमंत्रित अतिथियों सहित बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से चांपा तहसीलदार प्रशांत पटेल, नायब तहसीलदार श्री मार्बल, उप पंजीयक चांपा, तहसील अधिवक्ता संघ अध्यक्ष भीमन थवाईत, सचिव प्रहलाद राठौर, पूर्व अध्यक्ष विजय पटेल सहित वरिष्ठ अधिवक्ता डी.पी. अग्रवाल, नरेशधर दीवान, महेंद्र गुप्ता, ओमप्रकाश देवांगन, महावीर प्रसाद सोनी, रामखिलावन यादव, मनोज जायसवाल, रामकुमार कछुवाहा, शिवकुमार तिवारी, योगेश दुबे एवं बड़ी संख्या में अधिवक्ता व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन अधिवक्ता महावीर प्रसाद सोनी द्वारा किया गया।

बड़े डोंगर में श्रम पंजीयन शिविर का हुआ आयोजन, 107 श्रमिकों का हुआ पंजीयन

कोण्डागांव/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुरूप एवं कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिला कोण्डागांव में निर्माण श्रमिकों एवं असंगठित कर्मकारों के पंजीयन, नवीनीकरण तथा विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फरसगांव विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ेडोंगर में मोबाइल पंजीयन एवं नवीनीकरण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का आयोजन कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला कोण्डागांव द्वारा किया गया, जिसमें कुल 107 श्रमिकों का पंजीयन किया गया, वहीं 14 नवीनीकरण किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 01 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। शिविर में नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लाभ, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अधिकारियों ने श्रमिकों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की।

पीएम में देरी पर भड़का आक्रोश शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

सुकमा/ मूक पत्रिका

जिले के किरकिपाल निवासी फूल कुमार बघेल की नदी में डूबने से हुई मौत के बाद पोस्टमार्टम में हो रही देरी को लेकर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। मृतक के शव को पहले छिंदगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां से उसे सुकमा जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन घटना के एक दिन बाद भी पीएम नहीं हो सका।

पीएम में देरी से नाराज परिजन और स्थानीय लोग गुरुवार को सड़क पर उतर आए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय और जिला अस्पताल के सामने शव को सड़क पर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि एक गरीब परिवार के मृतक का समय पर पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाना स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है। प्रशासन की उदासीनता के कारण परिजनों को घंटों नहीं बल्कि पूरे दिन से अधिक इंतजार करना पड़ा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी।

कांकेर पुलिस की सख्तीः बस संचालकों को यातायात नियमों के कड़े पालन के निर्देश, शहर में लागू होगा नया ट्रैफिक रेगुलेशन प्लान

कांकेर/ मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर :- उत्तर बस्तर कांकेर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा (भा.पु.से.) के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बस संचालकों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार साहू, प्रशिक्षु आईपीएस (थाना प्रभारी कांकेर) प्रतीक दादासाहेब बनसोड़े, उप पुलिस अधीक्षक डॉ. मेखलेन्द्र प्रताप सिंह, यातायात प्रभारी दीपक साव और कलेक्ट्रेट से लोकेश सिन्हा (ष्ठक्रहृ) सहित बस संचालक और यातायात पुलिस बल उपस्थित रहे।

नया ट्रैफिक रेगुलेशन प्लानः निर्धारित हुए बस स्टॉपेज-शहर में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए रूट के अनुसार स्टॉपेज निर्धारित किए गए हैं। अब बसें केवल इन्हीं स्थानों पर रुकेंगीः

रायपुर रूटः मकड़ी चौक, चौक और बस स्टैंड।जगदलपुर रूटः ज्ञानी चौक और बस स्टैंड ।शहर के प्रमुख स्टॉपः पीजी कॉलेज, घड़ी चौक और ज्ञानी चौक।चेतावनीः मस्जिद चौक पर बस खड़ी पाए जाने पर सीधे चालानी कार्यवाही की जाएगी। संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं भी बस न रोकें और न ही अनावश्यक रूप से अधिक समय तक खड़ी रखें।

पुलिस ने बस संचालकों और चालकों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं:

1. ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंगः सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।2. नशे में ड्राइविंगः शराब पीकर वाहन चलाने पर लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

3. दस्तावेज और सुरक्षाः सभी चालकों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। साथ ही, बसों में फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य रूप से रखने होंगे।

4. प्रतिबंधित गतिविधियांः वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग और बसों में प्रेशर हॉर्न का उपयोग पूरी तरह वर्जित है।

5. फिटनेस और परमिटः सभी वाहनों के फिटनेस और परमिट नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।

पुलिस प्रशासन ने सभी बस संचालकों से अपील की है कि वे यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और गति सीमा का विशेष ध्यान रखें।

यातायात नियमों का पालन कर शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग प्रदान करें।

कांकेर : बारिश की भेंट चढ़ रहा किसानों का 'पीला सोना', लाखों क्विंटल धान का उठाव ठप : शिवसेना

कांकेर/ मूक पत्रिका

विक्रम ठाकुर :- कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर धान खरीदी केंद्रों में उठाव की सुस्त रफ्तार ने किसानों और समितियों की चिंता बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश के कारण खुले आसमान के नीचे रखा लाखों क्विंटल धान भीगकर खराब होने की कगार पर है। इस गंभीर समस्या को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों ने भानबेड़ा धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण किया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। शिवसेना प्रदेश सचिव महेश वासुदेव दुबे ने निरीक्षण के दौरान चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि भानबेड़ा केंद्र में कुल खरीदीः 39,691.60 क्विंटल कुल उठावः मात्र 11,846.22 क्विंटल (संग्रहण केंद्र और राइस मिल मिलाकर) वर्तमान में शेषः 27,845.38 क्विंटल धान अब भी केंद्र में पड़ा है। सिर्फ भानबेड़ा ही नहीं, बल्कि कच्चे, भानुप्रतापपुर, हाटकोंदल, और दमकसा जैसे केंद्रों में भी उठाव न होने से स्थिति बदतर बनी हुई है।

महेश वासुदेव दुबे ने प्रशासन को आगाह करते हुए कहा कि लगातार हो रही बेमौसम बारिश से धान में नमी बढ़ गई है और कई जगहों पर अंकुरण (धान का जमना) शुरू हो गया है। यदि उठाव में और देरी हुई, तो राइस मिलर्स इस नमी युक्त धान को स्वीकार करने से मना कर देंगे। इसका सीधा आर्थिक नुकसान समितियों और अंततः किसानों को उठाना पड़ेगा। खुले में रखे धान में फंगस लगने का डर भी बना हुआ है। निरीक्षण के बाद शिवसेना ने जिला प्रशासन और खाद्य विभाग से निम्नलिखित मांगें की हैंः तत्काल उठावः राइस मिलर्स के माध्यम से केंद्रों में फंसे धान का उठाव शुरू हो। तब तक धान को बचाने के लिए पर्याप्त तिरपाल और शेड की व्यवस्था की जाए। समय सीमा का निर्धारणः समितियों में जाम पड़े धान के उठाव के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की जाए।शिवसेना ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया, तो करोड़ों रुपये का धान बर्बाद हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान संत पटेल, भोला नेताम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की मेहनत की उपज को इस तरह बर्बाद होते नहीं देखा जा सकता और इसके लिए सीधे तौर पर विभाग की लापरवाही जिम्मेदार है।

रवान में मासूम से मारपीट का मामला गरमाया, समाज में आक्रोश; दोषियों पर

सिमंगा/ मूक पत्रिका

बलौदाबाजार क्षेत्र के ग्राम रवान में स्थित अंबुजा अडानी प्लांट के सुरक्षा कर्मियों द्वारा एक 11 वर्षीय मासूम बालक के साथ कथित रूप से अमानवीय व्यवहार किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के बाद पूरे साहू समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम रवान निवासी 11 वर्षीय बालक दिनेश्वर साहू (पिता ङ्क स्वर्गीय पदुम साहू) के साथ प्लांट के सुरक्षा कर्मियों ने बेरहमी से मारपीट की। आरोप है कि बच्चे को उठाकर पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना के बाद परिजनों ने बच्चे का उपचार कराया, वहीं समाज के लोगों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। घटना के विरोध में पिछले चार दिनों से साहू समाज द्वारा लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। समाज के लोगों ने आरोप लगाया है कि मामले को दबाने के लिए कुछ लोगों द्वारा डराने-धमकाने का भी प्रयास किया जा रहा है, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। इसी क्रम में बुधवार 25 मार्च को जिला मुख्यालय स्थित साहू संघ भवन में समाज के प्रमुख लोगों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही, धमकी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी तत्काल कार्रवाई करने की बात कही गई। बैठक में उपस्थित समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई, तो व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई, जिसमें प्रशासन को ज्ञापन सौंपने, शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन और कानूनी कार्रवाई जैसे विकल्पों पर विचार किया गया। समाज के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित बालक को न्याय दिलाया जाए तथा दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की सडक निर्माण में ठेकेदार की घोर लापरवाही

रायगढ़ /मूक पत्रिका

खरसिया के बिंजकोट-दर्रामुड़ा गांव में रहने वाले लोग सालों से एक ही सपना देख रहे थे ङ्क कंपनी के मेन गेट से बाजार चौक, दर्रामुड़ा, जामपाली फाटक होते हुए कुरूंभांठा तक की सड़क बन जाए। धूल-धक्कड़, गड्ढों और कीचड़ में फंसकर रोजाना परेशान रहने वाले ग्रामीणों ने बार-बार आवाज उठाई। आखिरकार करोड़ों रुपये की स्वीकृति मिल गई और सड़क बनने की तैयारी शुरू हो गई। मेसर्स सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड कंपनी ने खरसिया के राकेश गर्ग को ठेका दे दिया। काम शुरू भी हो गया। ग्रामीणों ने सोचा कि अब उनकी मुसीबत खत्म हो जाएगी। लेकिन ठेकेदार की लापरवाही ने सारा माहौल बिगाड़ दिया।

ग्रामीण बताते हैं कि सबसे पहले तो ठेकेदार ने पुरानी प्रधानमंत्री सड़क (क्करूस्ङ्घ) को उखाड़ फेंका। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी चेतावनी के अब वह रास्ता पूरी तरह खुला और खतरनाक हो गया है। भारी वाहन रोजाना आते-जाते हैं। ट्रक, ट्रैक्टर, बस ङ्क सब गुजरते हैं। दिन में तो किसी तरह गुजर जाता है, लेकिन रात में हालत बहुत खराब हो जाती है। अंधेरे में गड्ढे नजर नहीं आते, धूल उड़ती है, पैदल चलने वाले, स्कूली बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर परेशान हैं। एक ग्रामीण ने बताया, ÷रात को निकलना मुश्किल हो गया है। धूल से सांस लेना दूभर हो जाता है। बच्चे स्कूल से लौटते समय डरते हैं।÷

ठेकेदार राकेश गर्ग ने काम शुरू तो कर दिया, लेकिन गति कछुए जैसी है। आरसीसी रोड बननी है, बड़ा काम है, फिर भी रोज थोड़ा-थोड़ा करके काम चल रहा है।

ग्रामीण ने आरोप लगाया की ठेकेदार ने न तो कोई साइन बोर्ड लगाया, न कोई बैरिकेडिंग की, न कोई सावधानी बरती जिसके कारण हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। कोई भी गाड़ी अनियंत्रित हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लोग पूछते हैं ङ्क काम मिल गया तो ठीक से क्यों नहीं कर रहे? सिर्फसड़क उखाड़कर छोड़ दिया है, पूरा काम कब पूरा होगा, इसका कोई अंदाजा नहीं।

कंपनी की तरफसे ठेका दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अब कंपनी प्रबंधन को भी इसकी चिंता नहीं दिख रही। सिविल विभाग के अधिकारी जैसे कुम्भकरण की नींद में सो रहे हैं। ठेकेदार को काम जल्दी पूरा करने के लिए कोई दबाव नहीं। ग्रामीण चाहते हैं कि सड़क बने, लेकिन इस तरह लापरवाही से नहीं। वे कहते हैं, ÷हमने इतने साल इंतजार किया, अब जब काम शुरू हुआ तो ठेकेदार इसे बिगाड़ रहा है।÷

फिलहाल गांववासी सिर्फएक ही बात चाहते हैं ङ्क सड़क बन जाए, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन सही तरीके से और जल्दी। ठेकेदार राकेश गर्ग से सवाल है ङ्क सड़क उखाड़कर छोड़ दिया, चेतावनी के निशान तक नहीं लगाए, काम इतना धीमा क्यों?

कंपनी प्रबंधन से भी पूछना बनता है ङ्क ठेका देने के बाद क्या निगरानी नहीं रखनी चाहिए? क्या ग्रामीणों की परेशानी उनकी नजर में नहीं आ रही? अब देखना होगा कि दोनों पक्ष क्या जवाब देते हैं। लेकिन ग्रामीणों की एक ही गुहार है ङ्क सड़क बननी चाहिए, जल्दी और सही ढंग से।

संपादकीय

कंपनियों और निजी अस्पतालों के गठजोड़ में फंसता आम आदमी का भरोसा

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में कहा कि निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का ऐसा मकड़जाल बन गया है, जो आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। यह विडंबना ही है कि जिस भरोसे की वजह से कोई व्यक्ति बीमारी का इलाज कराने किसी निजी अस्पताल में जाता है, वह उसके लिए एक नई परेशानी की वजह बन जाता है। भविष्य में इलाज का खर्च उठाने की राह आसान बनाने का भरोसा देकर बीमा कंपनियां लोगों को अपनी योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए तो तैयार कर लेती हैं, लेकिन जब इलाज पर हुए खर्च की भरपाई करने का वक्त आता है, तो उसमें कई तरह की अड़चन पेश कर दी जाती है या कई बार मना भी कर दिया जाता है। निजी अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच मिलीभगत के सहारे चल रही इस गड़बड़ी के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, लेकिन अब तक इस तरह के घोटालों पर रोक को लेकर सरकार की ओर से कोई ठोस सक्रियता नहीं देखी गई है। हाल ही में यह मसला संसद में उठाया गया, जिसमें सरकार से स्वास्थ्य बीमा कंपनियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की गई। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में कहा कि निजी अस्पतालों और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों का ऐसा मकड़जाल बन गया है, जो आम लोगों की कमर तोड़ रहा है। अक्सर ऐसे मामले देखे जाते हैं, जिसमें अस्पताल में मरीज की मौत हो जाती है और नियमों का हवाला देकर या अलग-अलग कारण बता कर बीमा कंपनी दावे को खारिज कर देती है। इलाज के दौरान अस्पताल में किसी मरीज की मौत हो जाती है, तो कई बार खर्च चुकाने में असमर्थ होने पर अस्पताल शव देने तक से इनकार कर देता है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में मरीज के परिजन किस तकलीफ से गुजरते होंगे। सवाल है कि बीमा कराने के लिए लोगों को आकर्षित करने के कारोबार को इजाजत देने वाले संबंधित सरकारी महकमे इस तरह की मनमानियों के खिलाफ क्या कदम उठाते हैं। इसी मसले पर एक अन्य राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि कंपनियां हर साल करोड़ों रुपए का प्रीमियम तो इकट्ठा करती हैं, लेकिन जब इलाज के बाद मरीज या उसके परिजन खर्च के भुगतान के लिए संपर्क करते हैं, तो वे अलग-अलग तकनीकी कारणों का हवाला देकर रकम का एक बड़ा हिस्सा काट लेती हैं। असल में कंपनियां जब लोगों को बीमा कराने का भरोसा दे रही होती हैं, तब नियम-शर्तों को बताने के मामले में स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं बरती जाती।

राष्ट्रीय दुर्भाग्य यह कि पहले मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजी नौकरशाहों ने भारत को जातीय, साम्प्रदायिक, भाषाई-क्षेत्र और लिंग के लिहाज से बांटकर निरंतर कमजोर रखने की जो साजिश रची, उसे अँग्रेजों के लाभुक इशारों पर चलने वाले भारत के आजादी कालीन नेताओं ने बहुमत प्राप्ति का लोकतांत्रिक आधार बना दिया। पहले अखंड भारत को खंडित किया और फिर जाति-धर्म-भाषा की तुष्टीकरण वाले अंग्रेजी कानूनों को हूबहू स्वीकार कर लिया। इससे सामाजिक विखण्ड की प्रक्रिया तेज हुई। चौंकाने वाली बात तो यह कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए समाजवादियों और राष्ट्रवादियों ने भी जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र से जुड़े जनभावनाओं को भड़काया और बहुमत पाकर सत्ता हथियाया। लेकिन भारतीयों की नीतिगत एकजुटता की बात मील का पत्थर बनकर रह गई। मतलबी सरकारें बदलती रहीं, भारत माता की आत्मा पर अनगिनत प्रहार जारी हैं।

आखिर नफरत भरे भाषण पर कब सजग और सक्रिय होंगे हमारे हुक्मरान? यक्ष प्रश्न

(कमलेश पांडे)

राष्ट्रीय दुर्भाग्य यह कि पहले मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजी नौकरशाहों ने भारत को जातीय, साम्प्रदायिक, भाषाई-क्षेत्र और लिंग के लिहाज से बांटकर निरंतर कमजोर रखने की जो साजिश रची, उसे अँग्रेजों के लाभुक इशारों पर चलने वाले भारत के आजादी कालीन नेताओं ने बहुमत प्राप्ति का लोकतांत्रिक आधार बना दिया।

नफरत भरे भाषण, किसी भी सभ्य समाज के लिए वैचारिक कैंसर और सामाजिक एड्स के जैसा जानलेवा है, लेकिन दुनियावी तर्ज पर भारतीय लोकतंत्र में भी यह एक बुनियादी राजनीतिक-सामाजिक फैशन बनता प्रतीत हो रहा है। कोढ़ में खाज यह कि बहुमत की भूखी संसद और उसके इशारे पर कुछ कुछ फैसले लेने के आदी बन चुके सुप्रीम कोर्ट ने आजादी के 8वें दशक में भी विषाक्त बयानबाजियों के खिलाफ कोई कड़ा राष्ट्रवादी स्टैंड नहीं लिया ताकि राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर अनवरत रूप से जारी साम्राज्यवादी वैचारिक हमले की धार कुंद की जा सके!

ऐसा इसलिए कि इनकी भी अपनी विवशता है! चूंकि पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले अधिकार संपन्न लोग ब्रितानी नौकरशाही और राजशाही के इशारे पर बने भारतीय संविधान को मानने को अभिशप्त हैं और अपनी व्यवहारिक और मौलिक सोच को ताखे पर रख चुके हैं, इसलिए हर जनतांत्रिक बीमारी लाइलाज हो चुकी है और भारत माता अपनी ही संतानों को निरंतर मुखाग्नि देते देते थककर बूढ़ी हो चली है।

राष्ट्रीय दुर्भाग्य यह कि पहले मुस्लिम शासकों और फिर अंग्रेजी नौकरशाहों ने भारत को जातीय, साम्प्रदायिक, भाषाई-क्षेत्र और लिंग के लिहाज से बांटकर निरंतर कमजोर रखने की जो साजिश रची, उसे अँग्रेजों के लाभुक इशारों पर चलने वाले भारत के आजादी कालीन नेताओं ने बहुमत प्राप्ति का लोकतांत्रिक आधार बना दिया। पहले अखंड भारत को खंडित किया और फिर जाति-धर्म-भाषा की तुष्टीकरण वाले अंग्रेजी कानूनों को हूबहू स्वीकार कर लिया। इससे सामाजिक विखण्ड की प्रक्रिया तेज हुई।

चौंकाने वाली बात तो यह कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए समाजवादियों और राष्ट्रवादियों ने भी जाति-धर्म-भाषा-क्षेत्र से जुड़े जनभावनाओं को भड़काया और बहुमत पाकर सत्ता हथियाया। लेकिन भारतीयों की नीतिगत एकजुटता की बात मील का पत्थर बनकर रह गई। मतलबी सरकारें बदलती रहीं, भारत माता की आत्मा पर अनगिनत प्रहार जारी हैं, लेकिन हमारी संसद और सुप्रीम कोर्ट प्रबुद्ध और सुसंस्कृत भारत के निर्माण की जगह यूरोपीय और अरबी कलह को भारत पर थोपने की मूर्खता प्रदर्शित कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

यह कितनी मूर्खतापूर्ण बात है कि आजाद भारत में गरीबी और अपराध को जातीय चश्मे से देखा जाता है, सवर्ण यानी सामान्य जाती विरोधी कानून बनाये जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय का जिक्र करते हुए वर्तमान और भविष्य के सवर्ण विरोधी सामाजिक अन्याय किये जाने के निकृष्ट जनतांत्रिक विचारों पर मोहर लगाता है। खासकर भारतीय संविधान से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद (14, 15, 19, 21, एससी/एसटी एक्ट की तर्क संभाव्यता, आदि) को भी विस्तार से देखने और इनपर पुनर्विचार की जरूरत है।

अन्यथा, देर सबेर सामान्य जातियों के बीच भी संसद और सुप्रीम कोर्ट का अप्रासंगिक होना तय है। यक्ष प्रश्न है कि आखिर बहुमत की राजनीति के लिए समाज को कब तक झुलसाया जाएगा, क्योंकि जब सहिष्णुता के विचार बदलेंगे तो व्यवस्था बदलते देर नहीं लगेगी! चूंकि प्रभावित पक्षों के लिए भारतीय संविधान का पक्षपाती दृष्टिकोण एक ऐसा मटमैला पन्ना है, जो जाति, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि में वैधानिक विभेद रचता है और उसे सामान्य जातियों के खिलाफ ऐतिहासिक सामाजिक अत्याचार का प्रतिफल करार देता है।

हैरत की बात है कि संविधान जिन लोगों को कानूनी संरक्षण देता है, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक उत्पातों पर से भी प्रशासन अपनी आंखें फेर लेता है, यह जमीनी हकीकत है, इसलिए कतिपय सवाल लाजिमी है। और जन चेतना में ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा का एक विशेष और संगठित स्तर बना है, इसलिए उसे अलग से चिह्नित कर रोकने की ज़रूरत है; जबकि कोर्ट का रुख उनके अनुभव को सामान्य मानकर छोटा करने जैसा लगता है।

इसके उलट, दूसरे तरफ से यह डर भी जताया जाता है कि अगर एक जाति को विशेष तौर पर नफरती भाषण के खिलाफ संरक्षित श्रेणी में रखा

बहरहाल, नफरती भाषण सम्बन्धी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड व्यावहारिक है, और संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी संतुलित और सही माना जा सकता है, लेकिन यह बिना विवाद के नहीं है– विशेषकर जातिगत भावनाओं के मामले में।

सवाल है कि नफरत भरे भाषण सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या था? तो जवाब होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण को अलग से जाति आधारित दंडनीय अपराध घोषित करने की भी याचिका पर विशेष निर्णय देने से इनकार कर दिया और याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने स्पष्ट कहा कि केवल ब्राह्मण ही क्यों, किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण स्वीकार्य नहीं है, यानी एक विशेष जाति को अलग सा हेट स्पीच खंड के तहत नहीं रखा जाना चाहिए। लिहाजा, नेताओं को भी इसी भावना से सख्त कानून बनाना चाहिए।

सवाल है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का यह स्टैंड तर्कसंगत है? तो जवाब होगा कि भारतीय संविधान और फिलहाल लागू कानून (जैसे दंड संहिता की धाराएँ, आईटी एक्ट, निर्वाचन कानून, आदि) में दंगे, भड़काऊ भाषण और जाति आधारित उत्पीड़न के खिलाफ पहले से ही दंड का प्रावधान है; लिहाजा, कोर्ट ने इन्हीं तंत्रों को इस्तेमाल करने पर ज़ोर दिया, बजाय एक नई जाति विशेष श्रेणी बनाने के।

मसलन, न्यायपालिका का यह तर्क रहा कि अगर हेट स्पीच को रोकना है तो वह समुदाय विशेष के लिए नहीं, बल्कि सभी समुदायों के लिए एक समान और संवैधानिक ढांचे में होना चाहिए, अन्यथा यह न्याय की बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ जाएगा। जहां तक आपत्तियाँ और चिंताएँ की बात है तो ब्राह्मण समुदाय के कुछ तबकों का तर्क है कि आज की राजनीतिक जाए, तो इसे राजनीतिक रूप से हथियार बनाया जा सकता है और अन्य पिछड़े या अल्पसंख्यक समुदायों के हेट स्पीच विरोधी बचाव को नरम करने का तर्क भी बन सकता है।

संक्षेप में यदि इस स्टैंड पर मूल्यांकन किया जाए तो सैद्धांतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड प्राकृतिक न्याय, समानता और घुमावदार राजनीतिक जातिगत हथियारबंदी से बचाव के लिए उचित और संयमित लगता है। हालांकि, व्यावहारिक तौर पर यह यह भी दिखाता है कि नफरती भाषण को रोकना सिर्फ एक जाति की शिकायत से उठकर इस तरह के घृणा विरोधी कानूनों की दृढ़ और निष्पक्ष अमलीकरण तक जाना चाहिए, चाहे निशाना कौन सा समुदाय हो।

कहना न होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समुदायों (खासकर धार्मिक और जातीय) के खिलाफ हेट स्पीच पर लगातार एक ही मूल सिद्धांत बनाए रखा है- धर्म/जाति के आधार पर घृणा फैलाने वाला भाषण अस्वीकार्य है, लेकिन इसका नियंत्रण समान रूप से लागू कानूनों से होना चाहिए, न कि हर समुदाय के लिए अलग अलग राजनीतिक कानूनी व्यवस्था बनाकर।

मुसलमान समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच- 21 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और कई राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, जो विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा भाषण देते हैं या भड़काऊ रैलियाँ करते हैं। इस आदेश का मुख्य तर्क था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण सम्प्रदायिक तनाव और हिंसा को बढ़ाता है, इसलिए पुलिस और प्रशासन को ऐसे मामलों में तुरंत स्न्नह्नक्रदर्ज करना और जरूरी धाराएँ लगाना चाहिए, उन्हें आम सियासी भाषण की छवि में नहीं ढकना चाहिए।

वैचारिक क्रान्ति के बिना शान्ति की पुनर्स्थापना असम्भव

(डा. रवीन्द्र अरजरिया)

विश्व में चल रहे वर्तमान संघर्ष के लिए भविष्यवक्ताओं ने बहुत पहले ही सचेत कर दिया था। परिस्थितियों से लेकर परिणामों तक की विवेचनायें निरंतर सामने आती रहीं। इन भविष्यवाणियों के अनेक बिन्दु अतीत में प्रमाणित भी होते रहे परन्तु तब आधुनिकता की चमक में डूबे लोगों ने अंधविश्वास कह कर इसका मुखौल ही उडाया है। वर्तमान समय में जनसंख्या के बढते दबाव के कारण अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंच गया है। शासक बनने की होड ने युद्ध के हालात निर्मित कर दिये हैं। भारतीय आदिग्रन्थों सहित विदेश के अनेक भविष्यवक्ताओं ने इस युद्ध और उसके विस्तार को लेकर क्रमबद्ध विस्तार की घोषणायें पहले से ही हैं। भारत की भूमिका को भी रेखांकित किया गया है। युद्ध का विस्तार केवल ईरान-अमेरिका-इजरायल, रूस-यूक्रेन, पाकिस्तान-अफगानस्तान जैसी स्थितियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि चीन-ताइवान, भारत-पाकिस्तान, भारत-बंगलादेश सहित खाडी के अनेक देश युद्ध के मुहाने पर खडे है। इन तनावों का युद्ध में परिवर्तित होने का समय की भी पूर्व घोषणायें की जा चुकीं हैं। प्राकृतिक प्रकोप, पर्यावरणीय समस्यायें, जीवन को पोषित करने वाली वस्तुओं का अकाल, खनिजों के अनुशासनहीन दोहन, वैचारिक नकारात्मकता, सत्य को सम्प्रदायों में विभक्त करके जीवन पद्धति थोपने के प्रयास, आस्था संकट की स्थितियां, आतंक के आधार पर सत्ता हथियाने की चालें जैसे अनगिनत कारक प्रकृति और जीवन को किस्तों में कत्ल करते रहे हैं परन्तु अब तो स्थितियां नियंत्रण के बाहर हो चुकीं हैं। संयुक्त राष्ट संघ जैसी संस्थायें लगभग अस्तित्वहीन हो चुकीं हैं। कोरोना काल में विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ जैसे उत्तरदायी समूहों द्वारा अपनाया गया पक्षपातपूर्ण रवैया किसी से छुपा नहीं है। भय का मनोविज्ञान ठहाके लगा रहा है। चारों ओर शक्ति के प्रदर्शन से गुलामों की संख्या बढाने की पहल रही है। अग्नेय शस्त्रों की बाढ आ गई है। मिसाइलों की बौछारों से न केवल जन-जीवन समाप्त हो रहा है बल्कि पर्यावरणीय स्थिति भी असंतुलित होकर हाहाकार कर रही है। परमाणु परीक्षणों की प्रतिस्पर्धा में नित नये आंकडे आ रहे हैं। संसार के ठेकेदार बनने वाले विस्तारवादी देशों की कुटिलता ने तूफानी गति पकड ली है। ऐसे में संसार के लगभग सभी देशों में आंतरिक कलह, गृह युद्ध और विघटन की स्थितियां निर्मित करने में कट्टरवादियों की बडी जमातें अपने विदेशी आकाओं की इच्छापूर्ति में तन, मन और धन से लगीं हुईं हैं। आतंकवादी संगठनों को पोषित करने वाले राष्ट स्वयं को धर्म विशेष का मसीहा बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में भारत की भूमिका पर सबकी नजरें लगी हुईं हैं। सनातन का वसुधैव कुटुम्बकम् का उद्घोष महोपनिषद के अध्याय 4 के श्लोक क्रमांक 71 में वर्णित है जिसमें समूचा संसार एक परिवार की तरह बताया गया है। इसी तरह गरुड़ पुराण के अध्याय 35.51 में सर्वे भवन्तु सुखिनः की अवधारणा को निरूपित किया गया है। प्रत्येक जीव मे दैवीय और आसुरी प्रवृत्तियां होती है। जब दैवीय प्रवृत्तियों यानी सकारात्मकता का बाहुल्य होता है तब वह जीव देववत हो जाता है और जब उसमें आसुरी प्रवृत्तियों यानी नकाराकत्मकता का बाहुल्य होता है तब वही असुर बन जाता है। सभी जीव जन्म से देवता ही होते हैं जिन्हें बाद में परिवार के संस्कार, शिक्षा और वातावरण के आधार पर ही असुर बना जाता है। इस तरह की प्रवृत्तियों के कारण ही आज विश्व शान्ति के लिए सनातनी विचारधारा आवश्यक ही नहीं बल्कि नितांत आवश्यक है। सभी धर्म गुरुओं ने एक ही तरह से निराकार परमात्मा को परिभाषित किया है जिसमें ज्योति पुंज की आराधना का क्रम ही आस्था की पहली सीढी माना गया है। भविष्यवक्ताओं ने इसी ओर स्पष्ट संकेत किया है कि शान्ति, सुख और समृद्धि के लिए सभी जीवों को इसी तरह की अवधारणा का आलम्बन करना पडेगा। जनसंख्या वृद्धि की असंतुलनकारी स्थितियां, जीव की शोषणकारी प्रवृत्तियां और भौतिक संपदाओं का संग्रह ही विनाश की पटकथा लिखेगी। वैचारिक प्रदूषण ही रक्तरंजित स्थितियां निर्मित करेंगी।

ड्रैगन ने चल दी है नई चाल, अब पानी से करेगा वार, भारत आखिर कैसे देगा जवाब?

बांग्लादेश में यह संख्या करोड़ों में है। चीन ने तिब्बत के यारलुंग सांगपो नदी पर जिस विशाल जलविद्युत परियोजना की शुरुआत की है, उसने एशिया की भू-राजनीति में हलचल नहीं बल्कि भूकंप ला दिया है। यह कोई साधारण बांध नहीं, बल्कि पानी के जरिये ताकत हासिल करने की खुली रणनीति है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी मार सीधे भारत और बांग्लादेश जैसे निचले देशों पर पड़ने वाली है।

(नीरज कुमार दुबे)

यह वही नदी है जो भारत में सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र बनती है और आगे बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती है। अकेले ब्रह्मपुत्र घाटी में भारत के करीब तेरह करोड़ लोगों की आजीविका इस नदी पर निर्भर है जबकि बांग्लादेश में यह संख्या करोड़ों में है। चीन ने तिब्बत के यारलुंग सांगपो नदी पर जिस विशाल जलविद्युत परियोजना की शुरुआत की है, उसने एशिया की भू-राजनीति में हलचल नहीं बल्कि भूकंप ला दिया है। यह कोई साधारण बांध नहीं, बल्कि पानी के जरिये ताकत हासिल करने की खुली रणनीति है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी मार सीधे भारत और बांग्लादेश जैसे निचले देशों पर पड़ने वाली है। इस साल की शुरुआत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने नववर्ष संबोधन में जब इस परियोजना का ऐलान किया तो दुनिया को साफ संदेश मिला कि चीन अब न तो पर्यावरण की चिंता करेगा और न ही पड़ोसी देशों की। करीब 167 अरब डॉलर की लागत से बन रही यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत योजना बताई जा रही है जिसकी क्षमता 67 से 80 गीगावाट तक आंकी जा रही है। तुलना करें तो यह थ्री गॉर्जेस बांध से भी लगभग तीन गुना बड़ी हो सकती है। यह वही नदी है जो भारत में सियांग और फिर ब्रह्मपुत्र बनती है और आगे बांग्लादेश में जमुना के रूप में बहती है। अकेले ब्रह्मपुत्र घाटी में भारत के करीब तेरह करोड़ लोगों की आजीविका इस नदी पर निर्भर है जबकि बांग्लादेश में यह संख्या करोड़ों में है। यानी यह परियोजना सीधे करोड़ों जिंदगियों पर असर डालने वाली है।

पानी पर कब्जा यानी भविष्य पर कब्जा – चीन इस परियोजना को हरित ऊर्जा का नाम दे रहा है, लेकिन असल खेल कहीं ज्यादा गहरा है। नदी के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण का मतलब है नीचे बहने वाले पानी पर नियंत्रण। और यही वह बिंदु है जहां यह परियोजना एक रणनीतिक हथियार बन जाती है।

विशेषज्ञों का साफ कहना है कि यदि चीन चाहे तो सूखे के समय पानी रोक सकता है और तनाव के समय अचानक छोड़ सकता है। इससे बाढ़ जैसी तबाही पैदा हो सकती है। यही वजह है कि भारत के पूर्वोत्तर में इसे वाटर बम कहा जा रहा है।

देना है। यदि किसी भी कारण से बांध को नुकसान पहुंचता है तो उसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकता है। ब्रह्मपुत्र की तेज धारा और विशाल जल प्रवाह इसे और भी खतरनाक बना देते हैं।

इसके अलावा नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बदलाव से

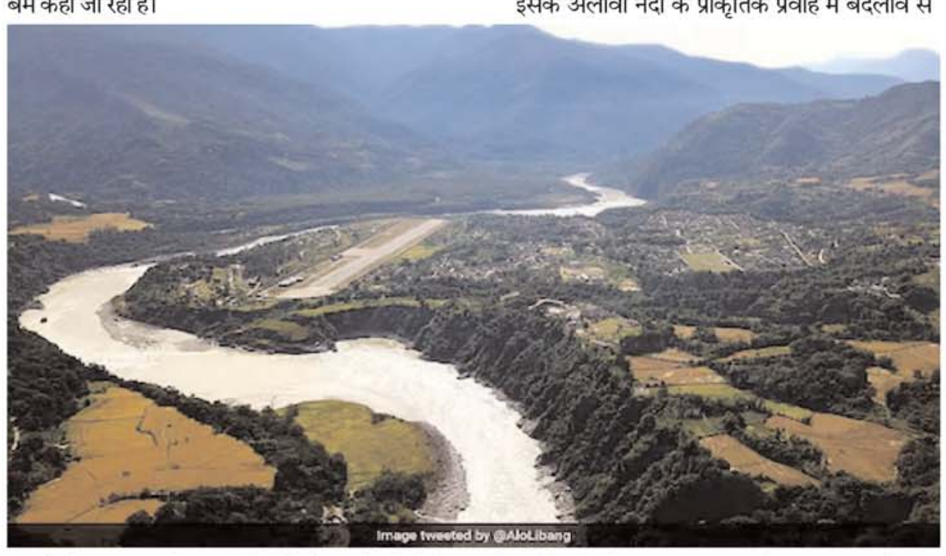

लोवी संस्थान की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि तिब्बत के पठार पर चीन का बढ़ता जल नियंत्रण भारत की अर्थव्यवस्था पर गला घोंटने वाला दबाव बना सकता है। यह केवल जल संकट नहीं बल्कि खाद्य संकट और ऊर्जा संकट को भी जन्म दे सकता है।

पर्यावरण के साथ खतरनाक खिलवाड़ – जिस इलाके में यह परियोजना बन रही है वह भूगर्भीय दृष्टि से बेहद अस्थिर है। यह क्षेत्र दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में गिना जाता है और यहां भूकंप तथा भूस्खलन आम बात है। ऐसे में इतनी बड़ी संरचना बनाना सीधे आपदा को निमंत्रण

पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ेगा। अनुमान है कि ब्रह्मपुत्र हर साल लगभग सात सौ मिलियन टन गाद लेकर आती है जो असम और बांग्लादेश की जमीन को उपजाऊ बनाती है। यदि यह प्रवाह बाधित हुआ तो खेती पर सीधा असर पड़ेगा।

तिब्बत की आवाज दबाकर बनाई जा रही परियोजना – इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चिंता पारदर्शिता को लेकर है। न तो पर्यावरणीय रिपोर्ट सार्वजनिक की गई है और न ही स्थानीय लोगों से कोई राय ली गई है। तिब्बती समुदाय और पर्यावरण कार्यकर्ताओं की आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने इसे चीन का दोहरा रवैया बताया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि चीन जब अपने हित में होता है तो अंतरराष्ट्रीय नियमों की बात करता है और जब नहीं होता तो उन्हें कुचल देता है।

भारत का पलटवार भी कम आक्रामक नहीं – चीन की इस चाल के जवाब में भारत ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। भारत पूर्वोत्तर में 208 बांध बनाने की योजना पर काम कर रहा है जिसकी कुल क्षमता 75 गीगावाट से ज्यादा होगी। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अपर सियांग है जिसकी ऊंचाई लगभग तीन सौ मीटर और क्षमता ग्यारह गीगावाट होगी। इसका मकसद केवल बिजली बनाना नहीं बल्कि चीन के जल नियंत्रण के खतरे को संतुलित करना है। भारत की योजना है कि वर्ष 2047 तक ब्रह्मपुत्र बेसिन से छिहत्तर गीगावाट से अधिक बिजली पैदा की जाए। यानी यह साफ है कि यह अब ऊर्जा की दौड़ नहीं बल्कि रणनीतिक टकराव बन चुका है।

पानी से डेटा तक फैलती जंग – अब यह संघर्ष केवल नदी तक सीमित नहीं रहा। जलविद्युत परियोजनाएं अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल नेटवर्क से जुड़ चुकी हैं। चीन अपने बांधों को स्मार्ट ऊर्जा तंत्र से जोड़ रहा है जबकि भारत भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी और डेटा विश्लेषण पर काम कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जो देश पानी को नियंत्रित करेगा वही ऊर्जा और डेटा दोनों पर नियंत्रण हासिल करेगा। यानी भविष्य की ताकत अब पानी और तकनीक के गठजोड़ में छिपी है।

बिना नियम के खतरनाक खेल – सबसे बड़ा खतरा यह है कि ब्रह्मपुत्र को लेकर भारत और चीन के बीच कोई औपचारिक जल समझौता नहीं है। यानी कोई बाध्यता नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। अतीत में चीन ने साल 2000 में आई बाढ़ के दौरान जरूरी आंकड़े साझा नहीं किए थे जिससे भारी नुकसान हुआ था। इससे भरोसे की कमी और गहरी हो गई है।

जिले में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण के प्रति हितग्राहियों को 10 हजार वितरित, इस योजना से 19,233 हितग्राहियों को मिला लाभ

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत जनपद पंचायत सारंगढ़ के सभाकक्ष में तहसील स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों और कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे द्वारा 15 भूमिहीन कृषक मजदूरों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक हितग्राही के खाते में 10 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्चुअल माध्यम से जुड़े और हितग्राहियों को संबोधित किया। जिले में इस योजना के तहत कुल 19,233 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। यह योजना ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में लागू है, जिससे भूमिहीन कृषक मजदूरों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे ने सभी हितग्राहियों को बधाई देते हुए योजना का लाभ उठाकर जीवन स्तर सुधारने की बात कही। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय, जनपद अध्यक्ष ममता ठाकुर एवं जनपद सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

बरमकेला के 900 हितग्राहियों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत बरमकेला के 900 हितग्राहियों के खाते में 10 हजार रुपये के मान से राशि अंतरित हुई। कार्यक्रम में सांकेतिक रुप से 7 हितग्राहियों को उनके खाते में राशि हस्तांतरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। जनपद पंचायत बरमकेला के सभाकक्ष में आयोजित ब्लॉक स्तरीय आदान राशि वितरण कार्यक्रम की मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष अजय नायक, जनपद अध्यक्ष डॉ विद्या चौहान, डॉ अभिलाषा नायक, सहोद्रा सिदार, राजू नायक उपाध्यक्ष नगर पंचायत, मनोहर पटेल, राजकिशोर पटेल, तरूण अग्रवाल, गजानंद गढ़तिया, जनपद सीईओ अजय पटेल, तहसीलदार पुष्पेंद्र कुमार राज, नायब तहसीलदार मोहनलाल साहू, पटवारी, नगर पार्षद, जनपद पंचायत सदस्य व, गणमान्य नागरिक सहित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाना है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए की वित्तीय सहायता सीधे हितग्राही के बैंक खाते में दी जाती है।

सरसीवां से लगभग 3 कीलोमीटर पर तिलाईपाली मोड बना दुर्घटना का गढ़

सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

सरसीवा से लगभग 3 कीलोमीटर दूर तिलाईपाली मोड दुर्घटना का गढ़ बन चुका है आपको बता दे सरसीवां से सारंगढ़ रोड पर स्थित यह मोड क्षेत्र के लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहा है फ़िर भी शासन प्रशासन को कोई ध्यान नहीं, यह खतरनाक मोड़ होने के बावजूद भी यहां कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, जैसे कि गाड़ी धीरे चलाएं, आगे खतरनाक मोड़ है, दुर्घटना जनित क्षेत्र आदि इस प्रकार का साइन बोर्ड होना चाहिए लेकिन इस मोड़ पर किसी भी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं है जिससे आए दिन यहां पर कोई ना कोई दुर्घटना हुआ रहता है, आज एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया ड्राइवर ने बताया कि रात में एक मोटरसाइकिल को बचाते बचाते ट्रक ड्राइवर अनियंत्रित हो गया वाहन क्रमांकछ्ग04क्ष5916 अनियंत्रित होकर पलट गया बलौदा बाजार से सीमेंट लेकर सारंगढ़ की ओर जा रहा था इस दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन

ट्रक पर लोड सीमेंट सब जमीन पर बिखर गया और ट्रक को भी नुकसान हुआ है, इससे शासन की लापरवाही भी कहा जा सकता है,

देखना यह है की खबर छपने के बाद शासन प्रशासन नींद से जगाता है कि नहीं

दैवीय पर्व पर नगर की मातृ शक्तियो का सम्मान

अंबागढ़ चौकी /मूक पत्रिका

दैवीय आराधना पर्व चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने नगरीय निकाय के अंतर्गतं विभीन्न क्षेत्रो में उल्लेखनीय कार्य करने वाली की नगर की मातृ शक्तियो को सम्मानित किया।

नगर पंचायत कार्यालय में नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने नगर के विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले तथा धार्मिक व आध्यात्मिक क्षेत्र व स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले नगर की मातृ शक्तियो को शाल, श्रीफ्ल एवं साडी भेटकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगर की सभी मंदिरो एवं धार्मिक आयोजनो में सेवा गीत के माध्यम में क्वांर एवं चैत्र नवरात्रि में सेवा करने वाली पटेल पारा महिला मंडल समिति का भी सम्मान किया। इसके अलावा स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र में सेवाए देने वाली मातृ शक्तियो को भी इस अवसर पर सम्मनित किया गया। नगर पंचायत में कार्यक्रम का शुभारंभ आदिशक्ति मातारानी की पूजा अर्चना कर किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ने नगर के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने वाली मातृ शक्तियो को नमन करते हुए कहा की नगर विकास में मिले उनके सहयोग के लिए नगर पंचायत सदैव ॠणी रहेगा। कार्यक्रम में सीएमओ विजय पांडेय, उपयंत्री योगेश्वर सिह ठाकुर, रामकुमार देवागन, पूर्व पार्षद प्रमोद ठलाल, पूर्व पार्षद श्रीमती उर्मिला पटेल, धनकुंवर पटेल, आशाबाई सहित काफी संख्या में नगर के विभीन्न वार्डो की माताए शामिल हुई।

श्रम व स्वाभिमान को मिला सम्मान - हारुन मानिकपुरी- वनविभाग के सुरक्षा श्रमिकों में खुशी की लहर

राजनांदगांव / मूक पत्रिका

श्रम आयुक्त दर वन कर्मचारी संघ के प्रांत प्रमुख हारुन मानिकपुरी ने वन मंडल अधिकारी राजनांदगांव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि वनों की सुरक्षा में लगे सैकड़ों सुरक्षा श्रमिक जो वर्षो से अल्प वेतन पर काम करते हुए संयुक्त परिवार में जीवन यापन कर वनों को अग्नि एवं कई प्रकार के अपराधों से बचाने का कार्य करते हैं। बिहड़ जंगलों में कार्यरत सुरक्षा श्रमिकों के पैर में जूता नहीं होने से उन्हें कांटा खुंटी चुभने से असहनीय परेशानियां होते हुए भी कार्य करने मजबूर रहते हैं। भीषण गर्मी के ऐसे मौसम में राजनांदगांव वन मंडल के कर्मयोगी वरिष्ठ अधिकारी गण सर्वश्री आयुष जैन जी वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव,उप वन मंडलाधिकारी श्री योगेश कुमार साहू जी सुरक्षा श्रमिकों को होने वाले तकलीफों को करीब से देखा और बिना देर किए सुरक्षा श्रमिकों के पैरों की सुरक्षा के लिए बहुत ही सुन्दर, मुलायम और टिकाऊ जूते वन परिक्षेत्र अधिकारी के माध्यम से श्रमिकों को दिए जिससे वनविभाग में कार्यरत सैकड़ों सुरक्षा श्रमिकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। श्री हारुन मानिकपुरी ने वनविभाग के उच्च अधिकारियों के आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नंगे पैर चलने से होने वाली चोटों और बिमारियों से बचाव होगा।

थरूण निषाद बने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ के नगरी ब्लॉक इकाई के उपाध्यक्ष

रायपुर/मूक पत्रिका

क्षेत्र के युवा एवं सक्रिय पत्रकार थरूण निषाद को छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की ब्लॉक इकाई में उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके चयन से क्षेत्र के पत्रकारों एवं समाजजनों में हर्ष का माहौल है। थरूण निषाद लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते रहे हैं। उनकी निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता को देखते हुए संगठन द्वारा यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। नवनियुक्त उपाध्यक्ष थरूण निषाद ने संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पत्रकारों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने तथा संगठन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान हेतु वे हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ पत्रकारों ने थरूण निषाद को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की है। सभी ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।

युवा सरपंच रमाकांत साहू का अनोखी पहल : मां वृंदा देवी मंदिर में 'बर्तन बैंक' से स्वच्छता की मिसाल

पाटन / मूक पत्रिका

पाटन विधानसभा क्षेत्र के खारू नदी के तट पर स्थित मां वृंदा देवी डिंडा कपाट आगेसरा में ग्राम पंचायत के युवा सरपंच रमाकांत साहू ने जनसहयोग से एक अनोखी पहल करते हुए स्वच्छता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मीडिया को जानकारी देते हुए सरपंच रमाकांत साहू ने बताया कि सामान्य चर्चा के दौरान उन्होंने अपने सरपंच साथियों के समक्ष मां वृंदा देवी मंदिर में 'बर्तन बैंक' बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पहल को तुरंत समर्थन मिला और रेवा राम साहू (सरपंच गातापार), जीवधन ठाकुर (सरपंच भनसूली) तथा अमित अग्रवाल (सरपंच बेल्हारी) ने प्रारंभिक सहयोग प्रदान कर बर्तन बैंक को मजबूत बनाया। आज स्थिति यह है कि मंदिर में भोजन व्यवस्था के लिए बर्तनों की कोई कमी नहीं है। हजारों श्रद्धालु एक साथ बैठकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं और कहीं भी दोना-पत्तल का उपयोग नहीं हो रहा है। जिससे स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन निरंतर जारी है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु भंडारे में भोजन ग्रहण कर रहे हैं।

दिल्ली में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)का जन आक्रोश रैली, मोदी सरकार पर तीखा हमला

अनूपपुर /मूक पत्रिका

भारत के कोने कोने से आए दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित माकपा की जन आक्रोश रैली में चिलचिलाती धूप को झेलते लाखों की तादाद में किसान, मजदूर, छात्र, नवजवान एवं महिलाएं सामिल हुए।

इस जन आक्रोश रैली में जिला अनूपपुर से सैकड़ों की संख्या में कामरेड इंद्रपती सिंह, कामरेड ओमप्रकाश,कामरेड रमेश सिंह, कामरेड रमेश परस्ते , कामरेड तेरसू सिंह , कामरेड सुमित्रा सिंह गोड़ कामरेड अनिल शर्मा, कामरेड मोतीलाल रजक के नेतृत्व में किसान, मजदूर,नौजवान, एवं महिलाएं शामिल हुए। महंगाई, बेरोजगारी, लेबर कोड, मनरेगा, बिजली संशोधन बिल और किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लोगों ने जोरदार आवाज उठाई। रैली में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार के वादे और जमीनी हकीकत में भारी अंतर है। देशभर से आए लोगों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि रोजगार, शिक्षा और खेती–तीनों संकट में हैं। यह रैली सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले सशक्त एवं निर्णायक संघर्ष की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। वक्ताओं ने मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि देश विरोधी नीतियों की ओर बढ़ते कदम पर रोक लगाएं अन्यथा खामियाजा भुगतने तैयार रहें। पेट्रोलियम पदार्थ एवं गैस सिलेंडर की देश में बढ़ते हुए संकट पर कहा कि मोदी सरकार के ग़लत विदेश नीति के कारण यह संकट पैदा हुआ है। जिसकी खामियाजा देशवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

उक्त आशय की जानकारी सीटू नेता कामरेड जुगुल राठौर ने दिया।

मुसालूर में कुम्हार समाज की बैठक सम्पन्न, विकास और परम्परा संरक्षण पर जोर

बीजापुर / मूक पत्रिका

कुम्हार समाज कल्याण संघ बीजापुर द्वारा ग्राम पंचायत मुसालूर के कुम्हार पारा में ग्रामीण स्तर की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तुमनार, दुगोली, तोयनार, बीजापुर और जैतालूर क्षेत्र के समाजजनों ने भाग लिया। बैठक में समाज के समग्र विकास, वर्तमान समय में हो रहे सामाजिक बदलाव और भविष्य की दिशा को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित रखने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य मेथूस कुजूर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज सभी समाज तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हर समाज के पास अपनी जमीन एवं सामुदायिक भवन हैं। सरकार हर समाज को दे रहा आप लोगों की मांगें बस्तर सांसद जल्दी पूरा करेंगे, वही जहां समय-समय पर बैठकें और विचार-विमर्श होते हैं। उन्होंने समाज को संगठित रहकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा अपनी परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का आह्वान किया।

बैठक में समाज के वरिष्ठ एवं प्रमुख लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई, जो समाज की जागरूकता का सकारात्मक संकेत है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रामचन्द्रम एरोला, अनिल कुमार नाग, काशीनाथ नाग, राजकुमार नाग, लच्छिन्दर नाग, रतीराम, दिनेश, आयतू, तुलसीराम, धनीराम, अनिल नाग, कमलू, कृष्णा, सुमित्रा, अनसूर्या, बलराम, लक्ष्मी आलम, मुन्नी आलम, सुशीला आलम, रमेश, बृजलाल नाग, चन्दन नाग, योगेश नाग, रमेश आलम, साम्रबत्ती नाग, गौरी नाग, पार्वती नाग, कमला नाग, लखमी नाग सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे।

फ्लाईएश परिवहन में नहीं कर रहे थे नियमों का पालन, रोड पर गिरा रहे थे राखड़

रुपाणाधाम, सारडा एनर्जी, महावीर, JSP पर 10 लाख का जुर्माना

रायगढ/मूक पत्रिका

फ्लाई एश का शतप्रतिशत यूटीलाइजेशन करने के लिए तीन साल की बाध्यता है। कोई भी पावर प्लांट इसका उल्लंघन करता है तो उसे कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए एश का मनमाना परिवहन किया जा रहा है। एसओपी का पालन किए बिना राखड़ परिवहन करने पर पर्यावरण विभाग ने पांच उद्योगों के विरुद्ध करीब 11 लाख रुपए का जुर्माना किया है। रायगढ़ जिले के लिए फ्लाईएश एक ऐसी परेशानी बन चुका है जिसका निराकरण सख्ती से किया जाना जरूरी है। इसके लिए एनजीटी के निर्देश पर सीपीसीबी ने गाइडलाइन बनाई है। तीन साल में उत्सर्जित पूरे फ्लाई एश का यूटीलाइजेशन करना अनिवार्य है। कंपनियों ने अपने संयंत्रों से उत्सर्जित एश को ठिकाने लगाने का काम ट्रांसपोर्टरों को सौंप दिया है। परिवहनकर्ता अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए तय जगह के बजाय कहीं भी डंप कर देते हैं। परिवहन के दौरान भी ट्रॉली से गीला फ्लाई एश रोड पर गिराते चले जाते हैं। पिछले दिनों पर्यावरण विभाग को शिकायत मिली थी कि सारडा एनर्जी ने खरसिया के बरगढ़ में शासकीय भूमि पर फ्लाई एश की अवैध डंपिंग की है। स्थल निरीक्षण में पाया गया कि छह ट्रक एश बिना अनुमति के डाला गया था। इससे आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण हो रहा था। सीईसीबी रायगढ़ ने सारडा एनर्जी पर प्रति टन 1500 रुपए की दर से 2.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह खरसिया से पलगढ़ा के बीच एनएच 49 का निरीक्षण किया गया। यहां भी सारडा एनर्जी ने ही छोटे देवगांव व बरगढ़ के बीच बिना अनुमति और बिना पोर्टल में एंट्री के एश का अवैध परिवहन व डंपिंग की। पूरे क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा था। सीईसीबी रायगढ़ ने सारडा एनर्जी पर 2,40,660 रुपए की क्षतिपूर्ति अधिरोपित की है।

रुपाणाधाम पर डेढ़ लाख का जुर्माना– तमनार के बरपाली गांव में बिना विधिवत अनुमति लिए रुपाणाधाम स्टील प्रालि ने फ्लाई एश डाल दिया था जिससे प्रदूषण हो रहा था। उद्योग जीएम आशीष तिवारी की उपस्थिति में निरीक्षण किया गया जिसके बाद कंपनी पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया गया। पर्यावरण विभाग ने डाले गए एश पर मिट्टी की परत बिछाने का भी आदेश दिया। महावीर एनर्जी एंड कोल बेनीफिक्रेशन ने भेंगारी में बिना अनुमति एश डाला। इस पर सीईसीबी ने 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

गीला फ्लाई एश ले जा रही थी जेएसपी की गाड़ियां– सीईसीबी के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जेएसपीएल के वाहन क्रमांक सीजी 04 क्यूबी 3580, सीजी 04 क्यूबी 3680, सीजी 04 क्यूबी 3180 से गीला फ्लाई एश रोड पर गिरता जा रहा था। तीनों वाहनों पर प्रकरण बनाकर जेएसपी पर 2,38,560 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जेएसपी के ही एक और वाहन जेएच 01 एफजी 0907 से भी गीला फ्लाई एश गिराया जा रहा था। इस पर 42,540 रुपए का जुर्माना किया गया। एनटीपीसी के वाहन क्रमांक सीजी 06 एचडी 9422 से भी गीला फ्लाई एश रोड पर गिरता जा रहा था। कंपनी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

संक्षिप्त समाचार

लश्कर-ए-ताइबा सरगना बिलाल आरिफ सराफी को परिवार वालों ने उतरा मौत के घाट

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान में आतंकी भर्ती में सक्रिय रहे लश्कर-ए-ताइबा के सरगना बिलाल आरिफ सराफी की उसके ही परिवार के लोगों ने हत्या कर दी। ईद की नमाज के बाद शनिवार को बिलाल पर चाकू से हमला किया गया और फिर उसे गोली मार दी गई। बिलाल पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुए लश्कर के मुरीदके स्थित मुख्यालय के पास हमला हुआ। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में बिलाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि बिलाल को उसके परिवार के लोगों ने ही मौत के घाट उतारा है। हालांकि, फिलहाल हत्या के असल कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूत्रों का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हो सकता है। खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, बिलाल लश्कर के मुरीदके स्थित मुख्यालय में प्रशिक्षण के लिए आतंकियों की भर्ती करता था। उसका काम युवाओं की पहचान कर उन्हें आतंकी संगठन के लिए तैयार करना था। इस दौरान वह लोगों का ब्रेनवॉश भी करता था। हालांकि, वह भारत में किसी मामले में वांटेड लिस्ट में शामिल नहीं था। पाकिस्तान, जिसने दशकों तक आतंकवाद नेटवर्क को अपनी विदेश नीति के हथियार के रूप में विकसित किया, अब खुद इसके शिकार बन गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार पाकिस्तान दुनिया का सबसे अधिक आतंक प्रभावित देश बन गया। 2025 में देश में 1,139 लोग मारे गए, 1,045 हमले हुए, 1,595 लोग घायल हुए और 655 लोग बंधक बनाए गए। दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान ही ऐसा देश है जहां 2025 में स्थिति बिगड़ी। पाकिस्तान में सबसे अधिक आतंकवादी घटनाएं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांत में हुई। यहां 74% हमले और 67% मौतें दर्ज की गईं। सबसे सक्रिय आतंकवादी समूह तेहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान रहा, जिसने 595 हमले किए और 637 लोगों की मौतों के लिए जिम्मेदार था।

ईरान के साथ शांति वार्ता चाहते हैं ट्रंप, संघर्ष विराम के लिए अमेरिका ने रखी छह शर्तें

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में बुरी तरह फंस गए लगते हैं। साथियों के साथ छोड़ने और घरेलू मोर्चे पर घिरने के बाद वह इससे निकलने के लिए सम्मानजनक रास्ता तलाश रहे हैं। उनकी टीम ईरान के साथ संभावित शांति वार्ता के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। अमेरिकी अधिकारी और सूत्रों के अनुसार, तीन सप्ताह के युद्ध के बाद ट्रंप प्रशासन ने अगले चरण पर प्रारंभिक चर्चा शुरू कर दी है। इस पर भी विचार-विमर्श चल रहा है कि ईरान के साथ शांति वार्ता किस स्वरूप में हो सकती है। सूत्रों के अनुसार, ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ संभावित कूटनीति पर चर्चा में शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं हुआ है। लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन ने दोनों देशों के बीच संदेशों को आदान-प्रदान किया है। ईरान ने बातचीत में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन कुछ बहुत कठोर शर्तों के साथ। ईरान की मांगों में युद्धविराम, भविष्य में ईरान पर हमला नहीं होने की गारंटी और मुआवजा शामिल है। शांति वार्ता और संघर्ष विराम के लिए अमेरिका ने भी ईरान के लिए छह शर्तें रखी हैं।

युद्ध से 50 लाख टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, कम प्रदूषित 84 देशों से भी ज्यादा

तेहरान, एजेंसी। युद्ध के चलते पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ा है। क्लाइमेट एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के पहले दो हफ्तों में करीब 50 लाख टन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। यह दुनिया के 84 कम प्रदूषण वाले देशों के कुल उत्सर्जन से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा उत्सर्जन नागरिक ढांचे के नुकसान से हुआ है। ईरान की राहत और बचाव एजेंसी रेड क्रिसेंट के अनुसार, हमलों में करीब 20,000 इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, जिससे 24 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध में इस्तेमाल लड़ाकू विमान, स्टेल्थ बॉम्बर व नौसैनिक बेड़े लगातार ऊर्जा खपत बढ़ा रहे हैं। तेहरान और अन्य इलाकों में तेल प्रतिष्ठानों पर हमलों से भी उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। इन हमलों में 25 लाख से 59 लाख बैरल तेल नष्ट

हुआ, जिससे करीब 18.8 लाख टन कार्बन उत्सर्जन हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, विमान, जहाज और अन्य सैन्य वाहनों के संचालन में 14 दिनों में 15 से 27 करोड़ लीटर ईंधन खर्च हुआ। इससे लगभग 5.29 लाख टन कार्बन उत्सर्जन हुआ। सैन्य उपकरणों के नुकसान से भी उत्सर्जन बढ़ा है। अमेरिका के चार और ईरान के 28 विमान नष्ट हुए, साथ ही 21 नौसैनिक जहाज और करीब 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए, जिससे लगभग 1.72 लाख टन कार्बन उत्सर्जन हुआ। मिसाइल और ड्रोन के उपयोग से अतिरिक्त 55,000 टन उत्सर्जन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल उत्सर्जन 50,55,016 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, जो कुवैत या आइसलैंड जैसे देशों के सालाना उत्सर्जन के बराबर है।

नेपाल की नदी में दो भारतीय किशोर लापता; इस्तांबुल में गैस विस्फोट के कारण एक शख्स की मौत

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के पालपा जिले में रविवार को एक नदी में तैरते समय भारत के दो किशोर कथित तौर पर बह गए। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के रहने वाले 17 वर्षीय फरान अंसारी और अमन अंसारी तिनाऊ नदी में तैरते समय लापता हो गए। सरकारी दैनिक गोरखापत्र ने पालपा जिला पुलिस सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। ये दोनों किशोर भारत से आए सात युवकों के एक समूह का हिस्सा थे, जो तानसेन नगरपालिका के तिनाऊ नदी तट पर आए थे। जिला पुलिस कार्यालय के सूचना अधिकारी होम प्रकाश चौधरी ने बताया कि उनमें से दो नदी के बहाव में बह गए। तलाशी अभियान शुरू किया गया लेकिन रविवार शाम तक कोई नहीं मिला। यह नदी नेपाल और भारत के तैराकों के बीच प्रसिद्ध है और कई लोग यहां मनोरंजन के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस नदी में इस तरह की दुर्घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। इस्तांबुल के मध्य फातिह जिले में प्राकृतिक गैस विस्फोट के कारण रविवार को दो इमारतें ढह गईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस्तांबुल के गवर्नर कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार खोज और बचाव कर्मियों ने 10 घायलों को बाहर निकाला, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। राज्यपाल दावुत गुल ने विस्फोट स्थल का दौरा किया और अस्पताल में बचे लोगों का हालचाल पूछा। इस्राइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इस्राइली बस्तियों में रहने वालों ने शनिवार की रात और रविवार की सुबह कई फलस्तीनी गांवों में उत्पात मचाया। इन लोगों ने कारों को तोड़ा, उनमें आग लगाई और कई लोगों को घायल कर दिया। फलस्तीनी आधिकारिक समाचार एजेंसी वाफा ने रविवार को कम से कम छह समुदायों में हुए हमलों की सूचना दी। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बताया कि जलुद गांव में कम से कम

पूर्व सांसद और अपने दोस्त के खिलाफ ही गवाही देंगे मार्को रुबियो, वेनेजुएला के लिए लॉबिंग करने का आरोप

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में मियामी से पूर्व सांसद डेविड रिवेरा पर वेनेजुएला सरकार के लिए गुप्त रूप से लॉबिंग करने के आरोपों से जुड़े संघीय मुकदमे की सुनवाई सोमवार से शुरू हो गई है। इस मामले में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो गवाही देंगे। दरअसल रुबियो, रिवेरा के पुराने दोस्त हैं और दोनों एक समय साथ रहे हैं। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि रिवेरा ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के लिए अमेरिका में समर्थन जुटाने के लिए लॉबिंग की थी। रिवेरा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में कोशिश की थी कि अमेरिका सरकार वेनेजुएला के खिलाफ सख्त कदम न उठाए। रिवेरा पर आरोप है कि उन्होंने वेनेजुएला की तत्कालीन विदेश मंत्री डेल्सी रोड्रिगेज (जो अब वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं) को प्रभावित कर वहां की तेल कंपनी पीडीवीएसए के माध्यम से 5 करोड़ डॉलर का लॉबिंग कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। मुकदमे के अनुसार, इस कथित विदेशी प्रभाव अभियान में टेक्सास के रिपब्लिकन सांसद पीट सेशंस और कार्टेल से जुड़े एक व्यक्ति ने भी रिवेरा की मदद की थी। यह मुकदमा इस बात को भी दर्शाता है कि मियामी कैसे लैटिन अमेरिका में अमेरिकी नीति को प्रभावित करता है। इसी संदर्भ में रुबियो की गवाही अहम मानी जा रही है। साल 2022 में दाखिल 11 बिंदुओं वाले आरोपपत्र में रिवेरा और उनके एक सहयोगी पर मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण नहीं कराने के आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन का कहना है कि अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए रिवेरा ने स्छु नाम का एक एन्क्रिप्टेड चैट ग्रुप बनाया था, जिसमें वेनेजुएला के मीडिया कारोबारी राउल गोर्रिन के साथ बातचीत होती थी। हालांकि 60 वर्षीय रिवेरा ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उनके वकीलों का कहना है कि उनकी कंपनी इंटरअमेरिकन कंसल्टिंग को पीडीवीएसए की अमेरिकी सहायक कंपनी ने नियुक्त किया था, इसलिए विदेशी एजेंट के रूप में पंजीकरण जरूरी नहीं था। इस मुकदमे में मार्को रुबियो की गवाही असाधारण मानी जा रही है। 1983 के बाद यह पहला मौका है जब अमेरिकी कैबिनेट का कोई मौजूदा सदस्य आपराधिक मुकदमे में गवाही देगा। हालांकि रुबियो पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन अभियोजन का कहना है कि रिवेरा उन्हें व्हाइट हाउस तक पहुंच बनाने के लिए एक अहम सहयोगी मानते थे। जांच के अनुसार, जुलाई 2017 में रिवेरा और रुबियो की वाशिंगटन में मुलाकात हुई थी, जहां रिवेरा ने दावा किया था कि मादुरो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं।

युद्ध की कीमत वसूलने की तैयारी में ईरान, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर लगाएगा करोड़ों की फीस

तेहरान, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी संकट गहराता दिख रहा है। अब ईरान ने वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर एक तय शुल्क लगाने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह शुल्क 20 लाख डॉलर (करीब 18 करोड़ रुपये) होगा। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरोजेर्दी ने बताया कि यह शुल्क लागू किया जा चुका है। अलाएद्दीन बोरोजेर्दी ने बताया कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर फीस लगाने का फैसला एक नए संप्रभु शासन की स्थापना का प्रतीक है। उन्होंने कहा, 'जलडमरूमध्य पार करने वाले कुछ जहाजों से आवाजाही शुल्क के रूप में 20 लाख डॉलर वसूलना ईरान की ताकत को दर्शाता है।' उन्होंने आगे कहा, 'युद्ध की एक कीमत होती है इसलिए स्वभाविक रूप से हमें ऐसा करना पड़ेगा।' बोरोजेर्दी की यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद सामने आई है, जिसमें ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से खोलने को कहा है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो वे ईरान के पावर प्लांट को निशाना बनाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि होर्मुज का रास्ता ईरान के दुश्मनों को छोड़कर बाकी सभी के लिए खुला है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी के बाद अब ईरान के सांसद ही होर्मुज पर भारी-भरकम शुल्क लगाने की बात कर रहे हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से करीब 20 प्रतिशत तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है। अगर यह रास्ता बंद होता है तो वैश्विक बाजार में तेल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। हाल के हमलों और तनाव के कारण पहले ही ऊर्जा बाजार में उथल-पुथल देखने को मिल रही है। ईरान की समुद्री सीमा पर मौजूद होर्मुज एक बेहद संकरा रास्ता है, जहां से वैश्विक तेल निर्यात होता है। ईरान इस रास्ते पर रणनीतिक बढ़त रखता है और इसे बाधित कर सकता है।

पूर्व पीएम इमरान खान का जेल से सख्त संदेशः कहा- आत्मा बेच चुके जजों को शर्म आनी चाहिए; बेटे कासिम ने क्या बताया?

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर पिछले कई दिनों से चिंता जताई जा रही थी। इसी बीच इमरान खान के बेटे कासिम खान ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में उनसे मुलाकात की। मुलाकात के बाद कासिम ने सोशल मीडिया पर अपने पिता का एक संदेश सोशल मीडिया पर साझा किया। इस संदेश में इमरान खान ने पाकिस्तान की न्यायपालिका और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इमरान खान ने अपने बेटे से भेजे संदेश में कहा, देश के जजों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यायपालिका अपनी आत्मा बेच चुकी है और उन्हें देश की एकता की कोई परवाह नहीं है। इमरान के मुताबिक, जब विरोधी उन्हें मानसिक रूप से नहीं तोड़ पाए, तो उन्होंने उनकी पत्नी बुशरा बीबी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने बुशरा बीबी के साथ हो रहे व्यवहार को अमानवीय और इस्लाम के खिलाफ बताया। इमरान ने कहा कि यह सब उन्हें ब्लैकमेल करने की एक साजिश है। इमरान खान ने जेल की मुश्किलों का जिक्र करते हुए बताया कि बेटों से 30 मिनट की मुलाकात के बदले उन्हें 24 घंटे अकेले (आइसोलेशन) रहना पड़ता है। उन्होंने जजों को गद्दार बताते हुए कहा कि जिन पर समाज के न्याय की जिम्मेदारी थी, वे ही धोखा दे रहे हैं। उन्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। बता दें कि इमरान खान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम लंदन में रहते हैं। उन्होंने पहले दावा किया था कि उनके पिता की दाहिनी आंख की रोशनी बहुत कम हो गई है और जेल प्रशासन इलाज में लापरवाही बरत रहा है। रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में कासिम ने यह भी कहा था कि सरकार उन्हें पाकिस्तान आने का वीजा नहीं दे रही थी क्योंकि उसे डर था कि इससे दुनिया का ध्यान इमरान खान की तरफ जाएगा। हालांकि, बाद में उन्हें वीजा मिल गया।

शटडाउन संकट में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, हवाईअड्डों की सुरक्षा में आव्रजन एजेंटों को उतारा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर डेमोक्रेकट्स को घेरते हुए कहा कि ईरान के पतन के बाद अब अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन कट्टरपंथी वामपंथी व बेहद अक्षम डेमोक्रेट पार्टी है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट हमारे देश को उन अवैध प्रवासियों के हवाले करना चाहते हैं जिन्हें उन्होंने हमारी बेहद मजबूत सीमा से घुसपैठ करने की अनुमति दी है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि सोमवार से आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) एजेंट हवाई अड्डों की सुरक्षा में लगे परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) की मदद करेंगे। शटडाउन संकट में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परिवहन सुरक्षा प्रशासन (टीएसए) की मदद के लिए सोमवार से आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) एजेंटों को तैनात करने का आदेश दिया है। आंशिक शटडाउन के कारण अमेरिकी हवाईअड्डों पर कर्मचारियों की कमी हो गई जिसका खामियाजा यात्रियों को लंबे इंतजार के रूप में उठाना पड़ रहा है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सोमवार को आईसीई हवाईअड्डों पर जाकर हमारे शानदार टीएसए एजेंटों की मदद करेगा। ये एजेंट इस तथ्य के बावजूद काम पर बने हुए हैं कि कट्टरपंथी वामपंथी डेमोक्रेट केवल हमारे देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले कट्टर अपराधियों की रक्षा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा एजेंट मुख्य रूप से हवाईअड्डों पर आव्रजन नियंत्रण का प्रबंधन करते हैं। टीएसए कर्मचारियों

की कमी के कारण हाल ही में यात्रियों को देश भर के हवाईअड्डों पर, विशेषकर सुरक्षा जांच में अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। पिछले महीने, आंशिक सरकारी कामकाज ठप होने के कारण लगभग 50,000 टीएसए सुरक्षा कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

हवाईअड्डे की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं आईसीई एजेंटः आईसीई एजेंटों को हवाईअड्डे की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। यह जिम्मेदारी टीएसए की है जिसके पास 65,000 कर्मचारी हैं। इनमें 50,000 हवाईअड्डा सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन के आव्रजन संबंधी कड़े अभियान में आईसीई ने केंद्रीय भूमिका निभाई है जिसकी वजह से कई डेमोक्रेट, नागरिक स्वतंत्रता समर्थक और आव्रजन वकालत समूहों ने इसकी आलोचना की है।

टीएसए के 400 से अधिक कर्मचारियों ने दिया इस्तीफाः डीएचएस ने कहा कि 14 फरवरी को आंशिक शटडाउन शुरू होने के बाद से 400 से अधिक टीएसए कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया है। शटडाउन के लंबा खिंचने के साथ इस्तीफा और छुट्टी लेने वालों की संख्या में काफी वृद्धि होने की आशंका है। ट्रंप के पूर्व सहयोगी व उद्यमी एलन मस्क ने शनिवार को टीएसए कर्मचारियों के भुगतान के लिए धन उपलब्ध कराने की पेशकश की थी।

डेमोक्रेट्स के फंड देने से इन्कार के बाद हुई समस्याः यह शटडाउन तब शुरू हुआ जब डेमोक्रेट्स ने गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) को फंड देने से इन्कार कर दिया जिसमें टीएसए और आईसीई दोनों शामिल हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य इस बात पर अड़े हैं कि जब तक डीएचएस हिंसक आव्रजन प्रवर्तन नीतियों में बदलाव नहीं करता तब तक फंड स्वीकृत नहीं किया जाएगा। वे मिनेसोटा में हुई हिंसक कार्रवाई का हवाला देते हैं। सत्तारूढ़ रिपब्लिकन ने डीएचएस के केवल गैर-आव्रजन प्रवर्तन विभागों के लिए फंड पारित करने के डेमोक्रेट्स के प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।

दक्षिणी प्रशांत महासागर में महसूस हुए भूकंप के झटके, कितनी रही तीव्रता?

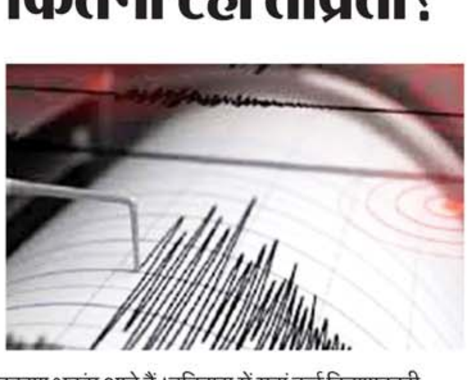

बीजिंग, एजेंसी। सतही भूकंप आम तौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि सतही भूकंपों की भूकंपीय लहरें सीधे सतह तक पहुंचती हैं, जिससे झटके अधिक तीव्र होते हैं और संरचनाओं तथा जनहानि का जोखिम बढ़ जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागर का यह क्षेत्र पृथ्वी के सबसे सक्रिय भूकंपीय बेल्ट, सर्कम-पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहां लगभग 81 प्रतिशत सबसे बड़े भूकंप आते हैं। इस बेल्ट के भीतर मुख्यत: टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और सबडक्शन (एक प्लेट के नीचे दूसरी का डूबना) के कारण भूकंप आते हैं। इतिहास में यहां कई विनाशकारी भूकंप हुए हैं, जैसे 1960 का चिली भूकंप और 1964 का अलास्का भूकंप। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं, जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती हैं और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है।

ईरान का अमेरिकी लड़ाकू विमान गिराने के दावे को यूएस ने बताया गलत

तेहरान, एजेंसी। मध्य पूर्व में तनाव के बीच ईरान ने एक अमेरिकी एफ-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, जिसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अमेरिका ने कहा, मध्य पूर्व में तैनात उसके सभी लड़ाकू विमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इससे पहले ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने होर्मुज द्वीप के पास एक अमेरिकी विमान को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से मार गिराया। तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी सेना ने अपने दक्षिणी तट के पास अमेरिकी स्न-15 को रोका और फिर उसे मार गिराया। रिपोर्ट में इसे ईरानी रक्षा बलों की एक बड़ी सफलता बताया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर ईरानी सेना को अमेरिकी विमान को रोकते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने ईरानी मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के दौरान अमेरिकी सेना ने 8,000 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं। इस पूरे अभियान में ईरान ने अमेरिका का कोई भी लड़ाकू विमान नहीं गिराया है। अमेरिका ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों को पूरी तरह झूठा करार दिया है। हालांकि, शुक्रवार को एक अमेरिकी एफ-35 स्टील्थ फाइटर को मध्य पूर्व में एक

अमेरिकी बेस पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। यह विमान एक मिशन के दौरान ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर से गुजरते समय निशाना बनाया गया था। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (आईआरजीसी) का दावा है कि उनकी सेना ने इस आधुनिक विमान को निशाना बनाया और इसे भारी नुकसान पहुंचाया। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में विमान का पायलट सुरक्षित बच गया था और आपातकालीन लैंडिंग के कारण का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

ईरान के अन्य दावेः यह घटना मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष में ईरान द्वारा अमेरिकी सेना के सबसे उन्नत और महंगे विमानों में से एक को निशाना बनाने का पहला ज्ञात मामला है। तेहरान ने यह भी दावा किया कि उसने 125 से अधिक अमेरिकी-इजरायली ड्रोनों को रोका और मार गिराया है। ईरान का कहना है कि यह उसकी मजबूत होती रक्षा प्रणाली का सबूत है।

राजस्थान रॉयल्स को मिलेगा नया मालिक

15000 करोड़ से अधिक की कीमत पर बिकेगी फ्रेंचाइजी

आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी डील

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 का सीजन शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही राजस्थान रॉयल्स को नया मालिक मिल गया है। अमेरिकी मूल के बिजनेसमैन काल सोमानी राजस्थान रॉयल्स की टीम को खरीदने जा रहे हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, सोमानी के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम (समूह) यह करार 1.63 बिलियन डॉलर (करीब 15290 करोड़ रुपये) में करने जा रहा है। यह डील आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी डील बन गई है। हालांकि, यह करार आईपीएल 2026 के बाद लागू होगा। यानी इस सीजन इसका स्वामित्व पुराने मालिक के पास ही रहेगा।

पिछले साल टोरेंट ग्रुप ने सीवीसी कैपिटल से गुजरात टाइटंस में 67 प्रतिशत मालिकाना हक हासिल किया था। यह करार 5025 करोड़ रुपये का था जिससे फ्रेंचाइजी की वेल्यू बढ़कर 7500 करोड़ रुपये हो गई थी। सीवीसी कैपिटल ने 33 प्रतिशत हक बरकरार रखा था। सीवीसी कैपिटल ने 2021 में गुजरात टाइटंस को 5625 करोड़ रुपये में खरीदा था।

कौन-कौन था दावेदार?- इस कंसोर्टियम में वॉलमार्ट परिवार से जुड़े रॉब वॉलटन और फोर्ड परिवार से जुड़े हैम्प परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। एरिजोना स्थित टेक उद्यमी कल सोमानी ने इन्ट्राएज, ट्रूयो डॉट एआई और एकेडेमियन जैसी कंपनियों की स्थापना की है। इस बोली में टाइम्स इंटरनेट के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम, आदित्य बिड़ला समूह और आर्सेलरमित्तल के सीईओ आदित्य मित्तल के नेतृत्व वाला मित्तल परिवार भी दावेदारों में शामिल थे। वर्तमान में ब्रिटिश-भारतीय कारोबारी मनोज बादले के पास टीम में 65 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने एक्स पर पोस्ट किया, 'राजस्थान रॉयल्स की टीम 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बिक गई है। लंदन स्पिरिट जो सबसे महंगी टीम है इसका मूल्य 370 मिलियन अमेरिकी डॉलर था जब द 100 में हिस्सेदारी बेची गई थी।' वहीं, एक कार्यक्रम के दौरान जब पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुशी जाहिर की। गांगुली ने कहा, आईपीएल के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये चौंका देने वाले आंकड़े है। पिछले 15 वर्षों में सोमानी ने एड-टेक, डेटा गोपनीयता, एआई गवर्नेंस और स्पोर्ट्स टेक पर केंद्रित उद्यमों की स्थापना और नेतृत्व किया है। यह पहली बार नहीं है जब सोमानी ने खेलों में रुचि जताई है। इससे पहले वह मोटर सिटी गोल्फ क्लब के सह-स्वामित्व और टीएमआरडब्ल्यू स्पोर्ट्स और टीजीएल गोल्फ लीग में निवेश कर चुके हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, राजस्थान रॉयल्स की बिक्री बीसीसीआई की मंजूरी के अधीन है और यह 2026 संस्करण के बाद प्रभावी होगी।

230 मैचों में कप्तानी की, 165 मैचों में जीत हासिल की

एकदिवसीय में सबसे सफल कप्तानों में नंबर-1 पर पोटिंग

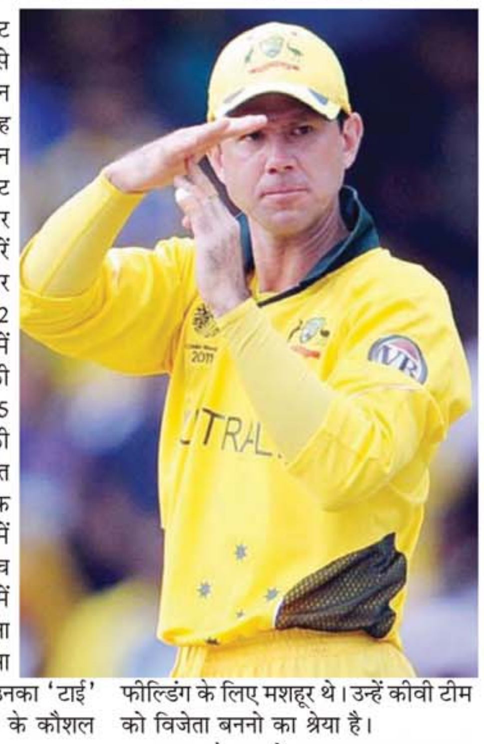

मुम्बई। एकदिवसीय क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग से लेकर न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग, भारत के महेन्द्र सिंह धोनी और श्रीलंका के अर्जुन रणतुंगा सहित कई कप्तान क्रिकेट जगह में छाये रहे हैं पर अगर सबसे सफल कप्तान की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पोंटिंग नंबर एक पर हैं। साल 2002 से 2012 के बीच पोंटिंग ने 230 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से उनकी कप्तानी ने टीम ने रिकॉर्ड 165 मैचों में जीत हासिल की। उनकी जीत का प्रतिशत 71.73 प्रतिशत रहा, जो अब तक सबसे अधिक है। पोंटिंग की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम केवल 51 मैच ही हारी है। उनके दौर में ऑस्ट्रेलियाई टीम काक हराना किसी के लिए भी असंभव सा काम था। 2.17 प्रतिशत का उनका 'टाई' रिकॉर्ड उनके मैच समाप्त करने के कौशल को दिखाता है।

वहीं न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। 1997 से 2007 के लंबे सफर में उन्होंने 218 मैचों में टीम की कमान संभाली थी पर उनका जीत का प्रतिशत 44.95 रहा टीम को उन्होंने 98 जीत दिलायी वहीं106 हार । इसके बाद भी उन्हें महान कप्तान इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने एक कमजोर टीम को बड़ी टीमों के स्तर तक पहुंचाया। है. फ्लेमिंग अपनी रणनीतिक समझ और स्लिप में अपनी फील्डिंग के लिए मशहूर थे। उन्हें कीवी टीम को विजेता बननो का श्रेया है।

भारत के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी 200 मैचों के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं. साल 2007 से 2018 के बीच धोनी ने भारतीय क्रिकेट को शीर्ष पर पहुंचाया। धोनी ने 110 मैचों में जीत दर्ज की और उनका जीत का प्रतिशत 55 प्रतिशत रहा।धोनी के नेतृत्व में टीम हालांकि 74 मैच हारी पर उसे जीत हासिल करना आ गया। दबाव के क्षणों में उनका शांत रहना और 0.5 प्रतिशत का टाई रिकॉर्ड उनकी मैच फिनिश करने की कला दिखाता है।

अभी टीम के लिए काफी कुछ करना चाहता हूं : स्टोक्स

जून में क्रिकेट सत्र शुरु होने के बाद बेहतर प्रदर्शन रहेगा लक्ष्य

लंदन। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज सीरीज में टीम की करारी हार के बाद भी कप्तान बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम को उनके पद पर बनाये रखा है। इससे पहले माना जा रहा था कि एशेज सीरीज में मिली 4-1 की हार के बाद कोच और कप्तान को को हटा दिया जाएगा। वहीं बोर्ड से मिले समर्थन से उत्साहित स्टोक्स ने कहा है कि वह वह अभी टीम के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं। जून में क्रिकेट सत्र शुरु होने के बाद उनका लक्ष्य और भी बेहतर प्रदर्शन करना रहेगा। स्टोक्स ने सोशल मीडिया में जारी एक बयान में , ' इंग्लैंड के क्रिकेट प्रशंसकों देश का कप्तान होना किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है जिसे वह हल्के मैं इसे हल्के में नहीं लेते। साथ ही कहा कि कप्तानी करते हुए अच्छे और खराब दोनों ही प्रकार के अवसर आते हैं। इसमें कभी खुशी और कमी गम भी मिलता है। खेल आपको पूरी तरह से अपने अंदर समा लेता है और कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बस यही एक चीज़ है। ' उन्होंने माना, पिछले 3 महीने मेरी कप्तानी के सफर का सबसे कठिन समय रहा है, इसने मुझे कई अलग-अलग तरीकों से परखा है और मुझे भरोसा है कि हर दूसरा कप्तान भी इससे गुजरा होगा। इसके बाद भी मैकलम, रॉब की और मुझमें इस टीम को आगे ले जाने का जुनून और इच्छा है, हम आपको वह सब कुछ देंगे जो हमारे पास है, हम जानते हैं कि हमने रास्ते में गलतियां कीं और हमने उन गलतियों से काफी कुछ सीखा है, आप सफलता से ज्यादा असफलताओं से सीखते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है पर सबसे जरूरी बात जो मैं प्रशंसकोंको बताना चाहता हूँ वह यह है कि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, मुझे यह टीम बहुत पसंद है, मुझे इंग्लैंड का कप्तान बनना बहुत पसंद है और मुझे इस भूमिका में देने के लिए बहुत कुछ है और मैं बहुत खुश हूं कि मुझे कप्तानी का अवसर मिला।

वैभव सूर्यवंशी सफल रहे तो रॉयल्स का जीतना तय है : अश्विन

पहले सत्र में सात मैचों में 252 रन बनाते हुए 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की थी

मुम्बई। दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने उभरते हुए बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा है कि अगर वह बड़ी पारी खेलता है तो राजस्थान रायल्स को जीत मिलनी तय है। वैभव ने गत वर्ष अपने पहले ही सत्र में आक्रामक बल्लेबाजी से सबको हैरान कर दिया था। अब उम्मीद है कि इस नये सत्र में वह और भी बेहतर बल्लेबाजी करेगा। वैभव ने अंडर-19 विश्वप में भी कई अच्छी पारियां खेली थीं जिससे भी उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में अश्विन कहा कहना है कि वैभव रॉयल्स के लिए किसी एक्स फैक्टर की तरह रहेगा। ऐसे में अगर वह क्रीज पर टिक गया तो रॉयल्स को बढ़े स्कारे स रोकना कठिन हो जाएगा। वैभव ने आईपीएल के अपने पहले सत्र में सात मैचों में 252 रन बनाते हुए 200 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज़ी की थी। इससे उनकी आक्रामक शैली का अंदाज होता है। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में शतक लगाया था। वह आईपीएल इतिहास में सबसे तेज़ शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज़ हैं। अश्विन के अनुसार वह इस सीज़न में रॉयल्स के लिए मैच में अंतर ला सकते हैं। साथ ही कहा कि वह अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में है, इसलिए उस पर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव डालना सही नहीं होगा। अश्विन के मुताबिक, मीडिया और सोशल मीडिया का ध्यान इस बार और ज्यादा रहेगा, जो मानसिक दबाव बढ़ा सकता है।अश्विन ने यह भी कहा कि इस बार विपक्षी टीमें सूर्यवंशी के खिलाफ बेहतर तैयारी के साथ उतरेंगी। पिछले सीज़न में उनकी निडर बल्लेबाज़ी ने गेंदबाज़ों को किया दिया था, पर अब उनके खेल का सभी को अंदाजा है। ऐसे में युवा बल्लेबाज़ के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अपनी आक्रामकता को बरकरार रखते हुए निरंतरता बनाये रखना।

हम केवल शामिल होने नहीं खिताब जीतने उतरेंगे : शुभमन

अपने पर भरोसा होने के कारण बने रहते हैं शांत

अहमदाबाद। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मुकाबलों में कठिन हालातों में भी शांत बने रहते है। शुभमन से जब इसका राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पर भरोसा है इसलिए व धैर्य से अपने अनुसार खेलते रहते हैं। इसके अलावा उन्हें अपनी टीम के साथ सुरक्षित महसूस होता है। गुजरात ने एक बार खिताब जीता है जबकि एक बार वह उपविजेता रही है ऐसे में अब शुभमन का लक्ष्य टीम को इस बार जीत दिलाना रहेगा। उनका कहन है कि हम केवल भाग लेने नहीं जीतने के इरादे से उतरेंगे। गिल ने में कहा, 'मैं स्वयं जैसा हूं और मेरे खेल और अपने समूह में जो विश्वास और सुरक्षा है, उसी से मेरे खेल में संयम आता है।' गुजरात टाइटंस की टीम अपना पहला मुकाबला 31 मार्च को गत उपविजेता पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलेगी। उसके बाद उसे 4 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है। शुभमन ने कहा, 'किसी भी हालात में शांत रहने से ही खेल आगे बढ़ने पर जीत की संभावना बनी रहती है।।' उन्होंने कहा कि मुख्य कोच आशीष नेहरा से उन्हें ये सीखने को मिला है। पिछले सत्र में गुजरात को एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस से हार का सामना करना पड़ा था। नेहरा ने कहा कि इस बार उनका ध्यान केवल खिताब जीतने पर रहेगा। उन्होंने कहा, 'इस सत्र में अलग तरह से सोचने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, खिलाड़ी सोचते हैं। उन्हें खेलना है, मैं बाहर बैठा हूं।' नेहरा ने कहा, 'पहले दिन से हमारी नीति साफ है। हम केवल शामिल होने नहीं जीतने के लिए यहां हैं। एक नई टीम के लिए यह सोचना आसान होता है कि इसमें समय लगेगा पर हमारा कभी भी ऐसा रवैया नहीं रहा।' गुजरात के लिए सकारात्मक पक्ष आशीष नेहरा जैसा कोच होना है जो टीम को लगातार बेहतर करने प्रेरित करते रहते हैं।

बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए जारी किये दिशा निर्देश

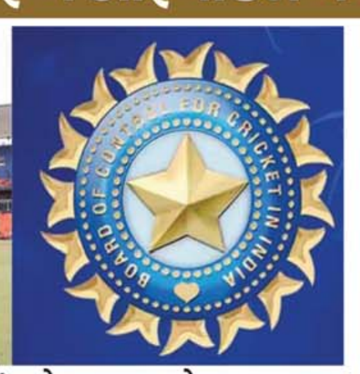

सभी खिलाड़ियों को करना होगा पालन

मुम्बई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल 2026 के लिए नये दिशा निर्देश जारी किये है। बोर्ड ने ये कदम इसलिए उठाया है जिससे खिलाड़ियों की मनमानी पर रोक लगायी जा सके। बीसीसीआई ने अपने नए आदेश में कहा है नये नियमों का पालन सभी को करना होगा। इसके तहत अब हर टीम के खिलाड़ी केवल टीम बस में ही यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा मैच के दिन किसी भी अभ्यास सत्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी अलग इंतजाम किया है, जहां टीमों को मेन चौक के दोनों तरफ अभ्यास के लिए दो-दो विकेट दिए जाएंगे। इस दौरान कोई भी टीम विरोधी टीम को दिए गए अभ्यास विकेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। टीम मैनेजर्स को नये दिशा निर्देशों की प्रति भेज दी हैं। इसमें कहा गया है कि टीमों को प्रैक्टिस एरिया में 2 नेट और मेन स्क्वायर पर 1 साइड विकेट मिलेगा, जहां वे रेंज हिटिंग कर सकें। मुंबई वेन्यू के लिए, अगर दोनों टीमें एक ही समय पर अभ्यास कर रही हैं, तो हर टीम को 2 पिचें मिलेंगी। वहीं कोई भी ओपन नेट अलाउड नहीं होगा। अगर कोई टीम अपना अभ्यास जल्दी खत्म भी कर लेती है तब भी दूसरी टीम को उस पिच का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। मैच के दिनों में किसी अभ्यास की अनुमति नहीं होगी।मैच वाले दिन मेन चौक पर कोई फिटनेस टेस्ट नहीं होगा। अभ्यास के दौरान केवल मान्यता प्राप्त स्टाफ को ड्रेसिंग रूम और फील्ड ऑफ प्ले में आने की अनुमति रहेगी। खिलाड़ी के परिवार के सदस्य और दोस्त अलग गाड़ी में सफर कर सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी एरिया से टीम का अभ्यास देख सकते हैं। एक्सटेंडेड सपोर्ट स्टाफ (थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट/नेट बॉलर) के लिए सूची बोर्ड को मंजूरी के लिए भेजनी होगी। मंजूरी मिलने के बाद, नॉन-मैच डे एक्रेडिटेशन जारी किए जाएंगे।

आईपीएल नहीं खेल पाये ये दिग्गज

नई दिल्ली। आईपीएल में खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है. इस लीग में दमदार प्रदर्शन के बूते कई खिलाड़ियों की किस्मत रातों-रात चमकी है. आईपीएल की चमक-धमक और करोड़ों की बोलियों ने दुनिया के लगभग हर बड़े क्रिकेटर को अपनी ओर खींचा है, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे 'दिग्गज' भी रहे हैं, जिन्होंने इस लीग में कभी नहीं खेला। इसमें ब्रायन लारा और जेम्स एंडरसन जैसे महान क्रिकेटर्स शामिल हैं, जिन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी अलग ही छाप छोड़ी. आइए ऐसे ही पांच खिलाड़ियों के बारे में आपको बताते हैं।

ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज)- आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था, जबकि ब्रायन लारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के ठीक बाद संन्यास ले लिया था. 2008 में जब पहला आईपीएल ऑक्शन हुआ, तब तक लारा क्रिकेट से लगभग दूर हो चुके थे. बहुत कम लोग जानते हैं कि लारा ने 2011 के आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम दिया था. उस वक्त उनकी उम्र 41 साल थी और उन्होंने अपना बेस प्राइस 400,000 (लगभग 1.8 करोड़ रुपये) रखा था. हैरानी की बात यह है कि इस महान बल्लेबाज पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई. हालांकि, भले ही लारा एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने आईपीएल से दूरी नहीं बनाई. वह सनराइजर्स हैदराबाद के साथ लंबे समय तक जुड़े रहे।

जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)- इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का नाम उन खिलाड़ियों में शुमार है, जिन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल सका है. एंडरसन ने 42 साल की उम्र में ऑक्शन में अपना नाम भी भेजा था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी. एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं.

स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड)- इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को भी आईपीएल में खेलने का कभी मौका नहीं मिल सका. ब्रॉड को साल 2011 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने खरीदा था, लेकिन चोट के कारण वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. इसके बाद ब्रॉड ने खुद ही आईपीएल से दूरी बना ली और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा प्राथमिकता दी.

एलिस्टर कुक- टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार एलिस्टर कुक टी20 क्रिकेट में उतने सफल नहीं हो सके. क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट कुक को खास रास नहीं आया. यही वजह रही कि वह कभी आईपीएल का हिस्सा नहीं बने. कुक इंग्लैंड की ओर से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने करियर में 12,472 रन बनाए.

कृषि महाविद्यालय बेमेतरा में छात्र संघ गठन शपथ ग्रहण समारोह एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

रेवेन्द्र सिंह वर्मा कृषि महाविद्यालय बेमेतरा में छात्र संघ गठन शपथ ग्रहण समारोह एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि माननीय श्री दीपेश साहू जी, विधायक बेमेतरा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि छात्र संगठन विभिन्न पृष्ठ भूमियों में छात्रों की एकता को प्रोत्साहित करता है और उनके बीच में समावेशी वातावरण निर्माण करता है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद से मानवीय मूल्यों में वृद्धि होती है एवं समाज विकसित होता है। विशिष्ट अतिथि श्री कपिल देव दीपक, कुल सचिव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने महाविद्यालय के प्रदर्शनी कक्ष, प्रयोगशाला, महाविद्यालय, प्रक्षेत्र का भ्रमण कर प्रोत्साहित करते हुए समन्वित कृषि प्रणाली के सांप सीढ़ी तथा मशरूम मॉडल को सराहा और कम लागत में उगने वाले मशरूम के बारे में बताया तथा युवाओं को प्रेरणा देते हुए छात्रों को भविष्य के लिए अभी से ध्यान देने की सलाह दी, और कहा कि छात्र संघ की गतिविधियां और नेतृत्व में भागीदारी से छात्रों के बीच टीम वर्क और कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है।अधिष्ठाता छात्र कल्याण इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर डॉ. संजय शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे उन्होंने छात्र संघ के कर्तव्यों के बारे में अवगत करवाया और छात्र संघ के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को कर्तव्य परायणता एवं अनुशासन का शपथ दिलवाया और कहा कि छात्र-छात्राओं को विभिन्न पृष्ठभूमियों में तन मन धन से सेवा करने की लिए तत्पर रहना चाहिए छात्र संगठन छात्रों की एकता को प्रोत्साहित करता है और उनके बीच में समावेशी वातावरण का निर्माण करता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. संदीप भंडारकर ने समस्त आगंतुकों को वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए वर्ष 2024-25 के शैक्षणिक गतिविधि व विभिन्न उपलब्धियों से अवगत कराया और कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन छात्र छात्राओं के जीवन को समृद्ध बनाने एवं आत्मविश्वास जगाने में मदद करता है। आयोजन से छात्रों को अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है और विशिष्ट छात्रों को हम उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करते हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री तोषण ठाकुर, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा उपस्थित रहे। इस तरह का आयोजन संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन में मुख्य भूमिका निभाती है। छात्र-छात्राओं द्वारा दिए गए विभिन्न मनमोहक व नयनाभिराम प्रस्तुतियों ने सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में डॉ. यू. के. ध्रुव, डॉ. टी. डी. साहू, डॉ. असित कुमार, कुंती बंजारे, डॉ. भारती बघेल, डॉ. हेमलता निराला, डॉ. प्रीति पैंकरा, राजेश्वरी कुर्रे, डॉ. साक्षी बजाज, श्रीमती प्रतिभा सिंह, डॉ. सरिता शर्मा, डॉ. महानंद, डॉ. रामेश्वर, संजीव गुर्जर तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारी एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

जिले में MSP पर चना खरीदी का शुभारंभ, पहले ही दिन 45 क्विंटल की खरीदी

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह खरीदी जिले की सेवा सहकारी समितियों में प्रारंभ की गई, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल देखा गया। अभियान के पहले दिन ही परपोड़ी एवं खण्डसरा स्थित सेवा सहकारी समितियों में कुल 3 किसानों से 45 क्विंटल चने की खरीदी की गई। किसानों ने शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ लेते हुए अपनी उपज का विक्रय किया और इस पहल की सराहना की। कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि वर्तमान में चना का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,875 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जिससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सकेगा। इसके साथ ही जिले में अरहर (तुअर) की खरीदी भी सुचारू रूप से जारी है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। कृषि विभाग, बेमेतरा ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का लाभ उठाते हुए अधिक से अधिक मात्रा में चना और अरहर का विक्रय निकटतम सहकारी समितियों के माध्यम से करें। विभाग का कहना है कि यह अभियान किसानों की आय बढ़ाने, फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। जिले में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत के साथ ही किसानों में विश्वास और उत्साह का माहौल दिखाई दे रहा है। प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर समितियों में पहुंचेंगे और इस योजना का लाभ उठाएंगे।

सिंघौरी स्कूल में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया,नवकन्या को कराया गया भोज

मां दुर्गा की नवरुपों का विधिविधान से की गई पूजा

बेमेतरा/मूक पत्रिका

शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला सिंघौरी में चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया।स्कूली बच्चे रंग बिरंगी पोशाक में तैयार होकर स्कूल पहुंचे थे तो वहीं प्राथमिक विभाग से कुछ बच्चे नवदुर्गा के रूप में तैयार होकर स्कूल पहुंचे थे।

संस्था प्रमुख सरस्वती साहू सहित समस्त स्टॉफ द्वारा इन नवकन्या की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिए एंव नवश्रृंगार भेट किया गया।साथ ही साथ केला,हलवा पूड़ी भी प्रसाद स्वरूप भोग लगाया गया।सरस्वती साहू द्वारा चैत्र नवरात्रि पर नवकन्या पूजा एंव कन्या भोज के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।इस दौरान स्कूल में धनीराम बंजारे संकुल समन्वयक सहित शशिकला यादव,देवेंद्र साहू,नुतेश्वर चंद्राकर, प्रशांत बघेल,किरण खरे,पूनम साहू,साजन वर्मा एंव 5वी परीक्षा में केंद्राध्यक्ष के रूप में आये शीतल राजपूत उपस्थित रहे।

सरिया पुलिस की कार्रवाईः 8 किलो से अधिक गांजा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सरिया पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 8 किलो 170 ग्राम गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में मादक पदार्थ तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है।

मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़े आरोपी-24 मार्च 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से ओडिशा की ओर से गांजा लेकर सरिया आ रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना के सामने घेराबंदी कर प्लेटिना मोटरसाइकिल क्रमांक छ्त्11 क्रू 7318 को रोका गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम हसन मोहम्मद (जिला बिलासपुर) और अलीम खान (जिला जांजगीर-चांपा) बताया।

तलाशी में मिला गांजा, लाखों की संपत्ति जब्त-तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल में रखी प्लास्टिक बोरी से 8 किलो 170 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 80 हजार रुपये बताई गई है। साथ ही एक मोटरसाइकिल, एक मोबाइल सहित कुल 1 लाख 40 हजार रुपये की संपत्ति जब्त की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका-यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे और डीएसपी संतोषी ग्रेस के मार्गदर्शन में की गई। थाना प्रभारी प्रमोद यादव के नेतृत्व में सउनि सुमन चौहान, प्रधान आरक्षक सत्यम मंडलोई, सुरेंद्र सिदार, विमल जांगड़े, दिलीप स्नेही, दिलीप साव, नर्मदा यादव, सूरज सिदार सहित पूरे थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

कलेक्टर डॉ कन्नौजे और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने किया ईवीएम का त्रैमासिक निरीक्षण

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ संजय कन्नौजे, एसडीएम सारंगढ़ वर्षा बंसल, डिप्टी कलेक्टर उमेश साहू, कांग्रेस से राधेलाल जायसवाल, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी से विकास टंडन सहित अन्य मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों ने सारंगढ़ के कृषि उपज मंडी प्रांगण स्थित निर्वाचन वेयरहाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान सभी ईवीएम के रखरखाव, भवन में बारिश के दौरान कोई सीपेज, सीसीटीवी कैमरा आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर निर्वाचन पर्यवेक्षक हरिकिशन डनसेना, लिपिक अविनाश सिदार सहित अन्य कर्मी उपस्थित थे।

डेढ़ साल के बचे की हत्या : पिता ने सिर पर मारा ईट,आरोपी पुलिस के हिरासत में जांच पड़ताल में जुटी पुलिस...

जांजगीर चांपा/मूक पत्रिका

जिले के ग्राम हिर्री पिता शिवाजी केवट ने अपने ही डेढ़ साल के बच्चे के ऊपर सिर पर ईट से हमला कर हत्या की है। हत्या की वजह स्पष्ट नहीं पाई है मगर दिमागी हालत ठीक नहीं है बताई जा रही है। पामगढ़ पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिए है मामले की जांच पड़ताल शुरू की है बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मिली जानकारी अनुसार,, बुधवार की सुबह 10 बजे आरोपी शिवाजी केवट (32 वर्ष) अपनी पत्नी से खाना मंगा नहीं मिलने पर गुस्से आ गया और खाट में लेटा डेढ़ साल का मासूम बच्चा अनुराग को अपने साथ लेकर घर के पास ही ईट से उसके सिर पर हमला कर हत्या कर दी। वही बचाव के लिए पहुंची बच्चे की दादी को भी ईट से हमला कर घायल कर दिया। आस -पास शोर गुल होने पर मोहले को लोगो के साथ परिजनों ने आरोपी शिवाजी को रस्सी से बंद दिया ताकि भागे नहीं। परिजनों का कहना है इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है पागलों की तरह करता है जिसका मेंटल अस्पताल में इलाज भी चल रहा है हर 6 महीनों में इंजेशन लगता है इस बार नहीं लगा था। घटना की जानकारी पामगढ़ पुलिस को मिलने पर मौके पर पहुंची और आरोपी शिवाजी को हिरासत में लिया गया। स्नस्रु की टीम को भी बुलाया गया जांच पड़ताल जारी है आरोपी पुलिस हिरासत है ।

खनिज शाखा की बड़ी उपलब्धिः लक्ष्य से दोगुना राजस्व, अवैध उत्खनन पर सख्त कार्रवाई

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में खनिज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025ड्ड26 में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष शासन द्वारा जिले को 450.00 लाख रुपये राजस्व का लक्ष्य दिया गया था, जिसके मुकाबले अब तक 901.00 लाख रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त किया गया है। यह निर्धारित लक्ष्य का लगभग 200 प्रतिशत है, जो विभाग की प्रभावी कार्यवाही और सतत निगरानी का परिणाम माना जा रहा है। जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। विशेष रूप से फरवरी और मार्च 2026 के दौरान खनिज विभाग ने सख्त अभियान चलाकर कई मामलों में कार्रवाई की है। खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत अवैध परिवहन के 31 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें कुल 7,90,100 रुपये की अर्थदंड राशि वसूल की गई। इसी तरह अवैध उत्खनन के 4 प्रकरणों में भी कार्रवाई करते हुए 8,05,500 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया है। विभाग द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन करने वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की सख्ती का स्पष्ट संदेश भी गया है। कलेक्टर कार्यालय की ओर से बताया गया है कि जिले में अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर आगे भी इसी तरह लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का उद्देश्य न केवल शासन के राजस्व में वृद्धि करना है, बल्कि खनिज संसाधनों का संरक्षण करते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना भी है।

राजेन्द्र शर्मा ने किया मार्गदर्शन

बेमेतरा में भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान

बेमेतरा/मूक पत्रिका

भारतीय जनता पार्टी बेमेतरा जिला के विभिन्न मंडलों में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान वर्ग 2026 के अंतर्गत उद्घाटन एवं समापन सत्र में पूर्व जिलाध्यक्ष एवं रायपुर शहर जिला भाजपा प्रभारी राजेन्द्र शर्मा शामिल हुए। इस अवसर पर राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि यह प्रशिक्षण वर्ग पार्टी संगठन को वैचारिक रूप से सुदृढ़ करने और कार्यकर्ताओं को संगठन की नीतियों, सिद्धांतों एवं कार्यप्रणाली के प्रति अधिक जागरूक एवं दक्ष बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ नेताओं एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। इनमें पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना, सेवा, सुशासन, राष्ट्र निर्माण में कार्यकर्ताओं की भूमिका, सामाजिक समरसता, अंत्योदय के सिद्धांत एवं वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। राजेन्द्र शर्मा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी भारतीय राजनीति और समाज के लिए मार्गदर्शक हैं। उनके ÷अंत्योदय÷ और ÷एकात्म मानववाद÷ के सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी की मूल आत्मा हैं, जिनके आधार पर पार्टी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व और कार्यक्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे कार्यकर्ताओं में वैचारिक स्पष्टता, संगठन के प्रति समर्पण और जनसेवा की भावना और अधिक मजबूत होती है।

उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पार्टी की रीति-नीति को आत्मसात करते हुए जनसेवा में सक्रिय भूमिका निभाएं और केंद्र की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने इस महाभियान को संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आशिष कुमार कंठले द्वारा कलयुग का भारत द्वारा अग्रदूत कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, भाजपा कार्यालय के पास, रायपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)-492001 से मुद्रित एवं वार्ड नंबर 18 बाजार पारा बेमेतरा पोस्ट व जिला बेमेतरा छ.ग. पिन कोड 491335 से प्रकाशित । संपादक आशिष कुमार कंठले समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार मो. नं. 7999238079, 7828658259, समस्त विवादों का निपटारा बेमेतरा न्यायालय होगा।